

घटना घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...



www.ghatatighatana.com

अम्बिकापुर, वर्ष 22, अंक - 347- सोमवार 19- अक्टूबर 2026, पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रुपये

RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050, डाक पंजीकरण. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

ग्वालियर में ट्रक ने 41 श्रद्धालुओं को कुचला...15 मौतें, 26 घायल

शीतला माता के दर्शन के लिए लाइन में खड़े थे, 9 अफसर सस्पेंड

ग्वालियर, 18 अक्टूबर 2026। ग्वालियर में तेज रफ्तार ट्रक ने 41 श्रद्धालुओं को कुचल दिया। हदसे में 15 लोगों की मौत हो गई। दो पुलिसकर्मियों समेत 26 लोग घायल हैं। हदसा चीनौर रोड पर ढलान के पास हुआ। सभी श्रद्धालु शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए सड़क किनारे लाइन में लगे थे। तभी चीनौर की ओर से आ रहा धान से भर ट्रक करीब 90 डिग्री के ढलान पर बेकाबू हो गया। ड्राइवर गुगल मैप की मदद से ट्रक चला रहा था। ढलान पर ट्रक पुलिस चेकपोस्ट तोड़ते हुए लोगों को कुचलकर मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से आ टकराया। इससे मंदिर की दीवार छह गई। कई लोग मलबे में दब गए। घायलों को जयराज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हदसे के बाद परिजन ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर और ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था। सरकार ने सिटी एसपी को हटा दिया है। 8 अफसर-पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया गया है। इनमें चार टीआई हैं। हदसे में जान गंवाने वाले एक युवक की बहन ने



कहा- हम पांच लोग दर्शन करने आए थे। एक बार दर्शन के बाद चार लोग दोबारा दर्शन करने जाने लगे। भाई बोला कि मैं गेट पर ही रहूंगा। तुम लोग दर्शन कर आओ, तभी ट्रक आया और घटना हो गई। हदसे में जान गंवाने वाले युवक दिव्यांश की मां का आरोप है कि उनकी बेटी बूढ़े के लिए गई, लेकिन पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया। ग्वालियर सिटी

एसपी रवि भदौरिया ने कहा...ट्रक के ड्राइवर और मालिक को हिरासत में ले लिया गया है। ड्राइवर नशे में थे या नहीं, उनका मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह ट्रक डबरा मंडी से धान लेकर आ रहा था। दो ट्रक एक साथ आ रहे थे। इस रूट पर कभी भारी वाहन नहीं आते थे।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताया दुःख

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए सड़क हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने इस भीषण दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। प्रधानमंत्री ने पीएमएनआरएफ से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपये देने की घोषणा की। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुई सड़क दुर्घटना में लोगों की जान जाने की खबर दिल तोड़ने वाली है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूँ और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूँ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुए हादसे में लोगों की जान जाने की खबर से बहुत दुःख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।

कोलकाता के दुर्गा पंडाल में भगदड़ अब तक 19 की मौत, 25 घायल

हाई कोर्ट के जज की निगरानी में एसटीएफ जांच की मांग

कोलकाता, 18 अक्टूबर 2026। महासमो की कोलकाता के चौराहागान सार्वजनीन पूजा पंडाल में मची भगदड़ ने भीषण त्रासदी का रूप ले लिया। इस हादसे में रविवार सुबह तक 19 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 25 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। राज्य सरकार ने घटना पर सख्त रुख अपनाने हुए कड़े कदम उठाए हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा में लापरवाही के संदेह में पूजा समिति के आयोजकों और स्वयंसेवकों समेत 12 लोगों को हिरासत में लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने स्वास्थ्य मंत्री शाहदात मुखोपाध्याय के साथ कोलकाता मेडिकल कॉलेज पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, समो की शाम अचानक तेज बारिश शुरू होने और बाहर भारी ट्रैफिक जाम के कारण सैकड़ों दर्शनार्थियों ने एक साथ पंडाल के अंदर घुसने का प्रयास किया। इसी दौरान अंदर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सूचना मिलते ही दमकल, कोलकाता पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को कोलकाता मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान मृतकों का आंकड़ा 18 तक पहुंच गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर एक वर्तमान न्यायाधीश के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के गठन की अपील करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि रविवार को उच्च न्यायालय से इस त्रासदी की न्यायिक जांच का औपचारिक अनुरोध किया



जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और परिवार के एक सदस्य को ग्रुप-डी की सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। घायलों को 5-5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और राज्य सरकार उनके चुने हुए किसी भी निजी अस्पताल में मुफ्त इलाज का पूरा खर्च वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि सीसीटीवी फुटेज की सघन जांच की जा रही है और लापरवाही बरतने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस त्रासदी के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की स्थिति भी सवाल के घेरे में आ गई है। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान जूनियर डॉक्टरों के एक वर्ग ने बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर जमकर क्षोभ व्यक्त किया। जूनियर डॉक्टरों का आरोप है कि इतने बड़े और प्रमुख मेडिकल कॉलेज में कोई अपातकालीन ट्रेमा केयर सेंटर ही नहीं है और न्यूरो सर्जरी विभाग की हालत भी बेहद खराब है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के उस कदम पर भी कड़ी आपत्ति जताई जिसमें 7-8 गंभीर मरीजों को आनन-फानन में निजी अस्पतालों में रेफर कर दिया गया।

पंजाब : संगरूर में तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचला, 9 की मौत

पंजाब, 18 अक्टूबर 2026। पंजाब के संगरूर में लहरागाणा-जाखल रोड पर तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। इस तेज रफ्तार कार ने मजदूरों को कुचल दिया। इस हादसे में 9 मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी है। हादसे के समय सड़क पर करीब 23 महिला एवं पुरुष मजदूर काम कर रहे थे। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लहरागाणा पुलिस स्टेशन के (एसएचओ) इंस्पेक्टर जसकरण सिंह के मुताबिक इस दुर्घटना में नौ लोगों की जान चली गई है।



सड़क पर काम कर रहे थे मजदूर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक कई मजदूर सड़क किनारे काम कर रहे थे। इसमें पुरुष और महिलाएं भी शामिल थीं। इस दौरान सामने से आई एक बेकाबू कार ने उन्हें कुचल दिया, जिसमें 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने ही घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के साथ राहत-बचाव कार्य शुरू किया।

जो अपनी आजीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाए,

दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मृतकों के परिजनों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाए। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें।

मुझ पर कैसे किया तो मामला लीगल हो जाएगा, हर राज्य में वोट चोरी की बात कहता हूं, ज्ञानेश जानते हैं कीमत चुकानी होगी : राहुल

पणजी, 18 अक्टूबर 2026। राहुल गांधी ने रविवार को गोवा में कहा कि मैं हर स्टेट से कहता हूँ पीएम वोट चोरी करते हैं। लेकिन मुझ पर कोई केस दर्ज नहीं होता। क्योंकि, ये जानते हैं कि अगर केस हुआ तो मामला लीगल हो जाएगा और ये फंस जाएंगे। दिल्ली में हम कुछ ही समय में पीएम, गृहमंत्री से निपट लेंगे। काम जारी है। सरकार की एक्सपायरी डेट आने वाली है। आपने देखा है कि आजकल पीएम सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि देश का युवा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है। राहुल कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान 'गोय राखोन यात्रा' में शामिल होने गोवा पहुंचे थे। यहां कांग्रेस की 28 दिन लंबी यात्रा का समापन हुआ है। राहुल का पिछले 4 सालों में यह पहला गोवा दौरा है। इससे पहले 2022 में वह यहां आए थे। गोवा में अगले साल 2027 में विधानसभा चुनाव हैं।

राहुल बोले...दिल्ली में हम सरकार से जल्द निपट लेंगे

राहुल ने कहा- आप गोवा के बारे में सोचिए। दिल्ली में हम कुछ ही समय में हम पीएम मोदी, अमित शाह से निपट लेंगे। काम जारी है। एक्सपायरी डेट आने वाली है। आपने देखा है कि आजकल नरेंद्र मोदी सामने खड़े नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कि देश का युवा इनके खिलाफ खड़ा हो गया है।



राहुल बोले- हर एजुकेशनल सिस्टम में आरएसएस के लोग बैठे हैं...

राहुल ने कहा...पूरी दुनिया मानती थी कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम नंबर वन मॉडल का था। लेकिन, आज दिल्ली में स्टूडेंट्स को ही मारा जा रहा है। हर एजुकेशनल सिस्टम में इन्होंने बीजेपी और आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं। हाईटेक करप्शन, जमीन का करप्शन ये यहां करते हैं। जैसे पहले गुजरात में नरेंद्र मोदी का मॉडल था। वैसे ही गोवा में करप्शन का मॉडल है। इसे सिर्फ कांग्रेस ही खत्म कर सकती है।

राहुल बोले- देश में सबसे ज्यादा वोटरेजगरी गोवा में है...

राहुल ने कहा...पहले मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान को रद्द कर दिया। इनका यही काम है कि पैसा कैसे बनाएं। इनका यही काम है। गोवा की जनता को लूटने का, आपकी जमीन छीनकर अरबपतियों को देने का। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी गोवा में है। यहां के लोग गोवा छोड़कर विदेश जा रहे हैं। बीजेपी के लोग अरबपति बन रहे हैं। गोवा सीएम के एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया है। सबकुछ अदाणी, अंबानी को पकड़ दिया है। इनका यही काम है। क्योंकि, अरबपति इनकी मार्केटिंग करते हैं। इस देश में सबसे ज्यादा कहीं करप्शन है तो वह गोवा में है।

राहुल बोले...गोवा में सरकार आपकी जमीन छीन रही...

राहुल ने कहा- गोवा देश में सबसे सुंदर जगह है, सबसे अच्छा कल्चर है। लेकिन यहां भी सरकार आपकी जमीन छीनकर गोवा के जो बाहर के लोग हैं उनको करोड़ों में बेचती है। पहले मास्टर प्लान था, मास्टर प्लान को रद्द कर दिया।

राहुल बोले...ज्ञानेश कुमार रात में सो नहीं पाते

राहुल ने कहा...मैं हर स्टेट से कहता हूँ पीएम नरेंद्र मोदी वोट चोरी करते हैं। लेकिन मुझ पर कोई मामला दर्ज नहीं होता। क्योंकि, ये जानते हैं कि अगर केस हुआ तो मामला लीगल हो जाएगा और ये फंस जाएंगे। दिल्ली में ज्ञानेश कुमार सो नहीं पाते रात को। पीएम और अमित शाह को भी नींद नहीं आती। क्योंकि, वे जानते हैं कि आज नहीं तो कल उनसे न्याय लेगी। ये तीनों जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी से ये लोग नहीं बच सकते हैं। क्योंकि, हम संविधान के रखवाले हैं। कांग्रेस की 'गोय राखोन यात्रा' 22 सितंबर को शुरू हुई थी। इस यात्रा के तहत गोवा की सभी 40 विधानसभा सीटों पर पहुंचने का लक्ष्य रखा गया। पार्टी ने इसे गोवा की जमीन, पहचान, पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए चलाया गया।

भारत में भी रची गई थी बांग्लादेश और फ्रांस जैसी हिंसा की साजिश : किरन रिजजू



नई दिल्ली, 18 अक्टूबर 2026। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरन रिजजू ने रविवार को दावा किया कि भारत में भी ठीक वैसी ही हिंसा, आगजनी और लुटपाट की साजिश रची गई थी, जैसी हाल ही में बांग्लादेश और फ्रांस में देखने को मिली। भारत-विरोधी ताकतों और कुछ राजनेताओं पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत में सत्ता परिवर्तन विदेशी साजिशों से नहीं बल्कि केवल लोकतांत्रिक चुनावों से ही संभव है। रिजजू ने आरोप लगाया कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए एक सोची-समझी रणनीति तैयार की गई थी। उन्होंने कहा...भारत-विरोधी गिरोहों और कुछ राजनेताओं ने मिलकर युवाओं को भड़काने और देश को लोकतांत्रिक जड़ें बहुत मजबूत हैं। उन्होंने कहा, खतरनाक साजिश रचने वाले यह भूल गए कि भारत न तो बांग्लादेश है और न ही फ्रांस। विदेशी अरबपति जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हुए रिजजू ने विदेशी दखलअंदाजी को लेकर भी कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है लेकिन केवल चुनावों के जरिए, सोरोस के जरिए नहीं। उल्लेखनीय है कि विपक्षी दल, छत्र संगठन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को तत्काल बन्द करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में 5 राउंड फायरिंग, एक्टर सुरक्षित....

लॉरेंस गैंग की पोस्ट...जो सलमान के साथ काम करेगा, उसका यही अंजाम होगा

मुंबई, 18 अक्टूबर 2026। एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम 7 बजे मुंबई में फायरिंग हुई। एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने उन पर 5 राउंड फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, फुटबॉल खेलकर लौटते वक्त टाइगर की कार जुहु के पुष्पा पार्क के पास रुकी। यहां उन्हें देखने के लिए भीड़ जमा हो थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार तीन लोग वहां पहुंचे। हमलावरों ने टाइगर की गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। टाइगर के ड्राइवर और एक ऑटो-रिक्षा वाले को भी गोलियां लगी हैं। टाइगर श्रॉफ सुरक्षित हैं। हमले के बाद एक पोस्ट वायरल हो रही है,



जिसमें लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने फायरिंग की जिम्मेदारी ली। लिखा कि सलमान खान के साथ काम करने वाले का यही अंजाम होगा।

महाराष्ट्र-मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म-6 में बदलाव का प्रस्ताव भेजा कहा...ये न पूछा जाए कि पहली बार नाम जुड़वा रहे, लोग इससे डर रहे...

मुंबई, 18 अक्टूबर 2026। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म-6 में बदलाव का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा है। इससे एसएसआर में हटे वोटर दोबारा नाम जुड़वा सकेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि जो लोग वोटर लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाना चाहते हैं, ऐसे वोटर्स से पहली बार वोटर बनने की घोषणा न कराई



जाए। क्योंकि झूठी घोषणा पर एक साल तक जेल, जुर्माना या दोनों हो

सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि लोग इससे डर रहे हैं। कई बीएलओ ने भी इस बात की शिकायत की है। यह प्रस्ताव पिछले हफ्ते भेजा गया। महाराष्ट्र में स्कूल अभी चल रहा है। यहां ड्राफ्ट रोल से हटे पुराने वोटर्स को भी फॉर्म-6 से नाम जुड़वाने को कहा जा रहा है। फॉर्म-6 में अभी ये बताना होता है कि वह पहली बार मतदाता सूची

में नाम जुड़वा रहा है। फॉर्म में ये जानकारी देनी की बात पहली बार जोड़ी गई है। फॉर्म में यह भी घोषित करना होता है कि उसका नाम किसी विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल नहीं है। फर्जी घोषणा करने पर जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

महाराष्ट्र : बीड में बस और कार की टक्कर...5 मौतें, 1 की हालत गंभीर

बीड, 18 अक्टूबर 2026। महाराष्ट्र के बीड में तुलजापुर जा रहे श्रद्धालुओं को ले जा रही एक कार की राज्य परिवहन की बस से टक्कर हो गई। जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटनास्थल पर पुलिस पहुंची। स्थानीय लोगों ने सड़क निर्माण के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव का काम शुरू किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, साल 2024 में भारत में सड़क हादसों से 1.77 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसका मतलब है कि देश में रोज करीब 485 और हर घंटे लगभग 20 लोग जान गंवा रहे हैं। इन मौतों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार और हेलमेट या सीटबेल्ट न लगाना है।



मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026 इंदौर में 23-24 अक्टूबर को, जूटेंगे देश-विदेश के विशेषज्ञ

भोपाल, 18 अक्टूबर 2026। मध्य प्रदेश के इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आगामी 23 एवं 24 अक्टूबर को 'मध्यप्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026' का आयोजन किया जाएगा। दो दिवसीय समिट में देश-विदेश की सेमीकंडक्टर कंपनियों, निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और स्टार्टअप प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। आयोजन में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश, तकनीकी सहयोग, अनुसंधान, नवाचार और औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश को सेमीकंडक्टर उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने, तकनीकी अधोसंरचना विकसित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और कुशल मानव संसाधन तैयार करने पर विशेष ध्यान दे रही है। जनसंपर्क अधिकारी जूही श्रीवास्तव ने रविवार को बताया कि समिट में सेमीकंडक्टर विनिर्माण, चिप डिजाइन, उन्नत पैकेजिंग एवं टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अनुसंधान एवं नवाचार तथा कुशल मानव संसाधन विकास जैसे विषयों पर विचार-विमर्श होगा।

अराजकता के सहारे सत्ता परिवर्तन वाली हरकतें

नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन कर चर्चों में आई काकरोच जनता पार्टी ने जब संसद मार्च का आयोजन किया था,तब उसमें कैसी हिंसा हुई थी, यह किसी से छिपा नहीं। इस हिंसा से यह आशंका पैदा हुई थी कि सीजेपी समर्थक देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात पैदा कर सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। अब इस आशंका की पुष्टि होती दिख रही है। इसी कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरा। बीते दिनों एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि हाँ, हम सत्ता परिवर्तन के लिए लड़इ लड़ रहे हैं और ऐसा करके रहेंगे। नीट पेपर लीक के विरोध में सीजेपी के धरने में सक्रिय रहें नेहा बोरा ने भी कांग्रेस के प्रदर्शन में बड़-चढ़ कर भाग लिया। राहुल गांधी ने उन्हें आगे भी किया,जबकि वे सीजेपी की सहयोगी हैं और वामपंथी छत्र संगठन आल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आइसा की अध्यक्ष हैं। नेहा बोरा ने भी साफ कहा कि बांग्लादेश के छत्र आंदोलन ने उन्हें क्रांति का रास्ता दिखाया और वे उस आंदोलन से प्रेरणा लेती हैं। क्या इससे अधिक बेवकूी बात और कोई हो सकती है? कांग्रेस के साथ खड़े प्रशांत भूषण, नेहा बोरा के बयानों और सीजेपी नेताओं के अराजक रवैये से यह आशंका बलवती होती है कि देश में अस्थिरता पैदाकर सत्ता परिवर्तन की कोशिश की जा रही है। यह खतरनाक है कि खून-खराबे वाली क्रांति तक की बातें की जा रही हैं और बांग्लादेश के हिंसक आंदोलन को प्रेरक बताया जा रहा है। बांग्लादेश आंदोलन में कट्टरपंथी मजहबी और अराजकतावादी ताकतों की शामिल थीं।

इसी कारण वहां ऐसे हालात बने कि प्रधानमंत्री शेरख हसीना को जान बचाने के लिए भागकर भारत आना पड़ा। इसके बाद वहां उनके समर्थकों के साथ ही हिंदुओं की बड़े पैमाने पर हत्याएं हुईं। बांग्लादेश में हिंसा के बल पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जिसके नतीजे में अंतिम सरकार बनी, उसने इस देश को और अधिक अराजकता की आग में ही झोका।बांग्लादेश में वास्तविक सत्ता परिवर्तन चुनाव के बाद ही हुआ। लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन चुनावों से ही होता है,लेकिन राहुल गांधी के करीबी प्रशांत भूषण और नेहा बोरा अराजकता के सहारे सत्ता परिवर्तन की बातें कर रहे हैं। निःसंदेह हमारा संविधान विरोध प्रदर्शन का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं। संविधान शांतिपूर्ण विरोध पर बल देते है,लेकिन इसकी अमदेखी करके अराजक तौर-तरीकों की पैरवी की जा रही है। अराजकता के सहारे सत्ता परिवर्तन की बातें करीना संविधान का खुला निरादर ही है।

रावण की ऊँचाई नहीं,रावणी प्रवृत्तियों की करें खिंचाई

दशहरे का मौसम आते ही रावण की पूछ-परख बढ़ जाती है। साल भर समाज में रावण जैसी प्रवृत्तियाँ फलती-फूलती रहें,किसी की कोई ख़ास परेशानी नहीं होती, ले कि न दशहरा आते ही रावण के पुतले की ऊँचाई पर बहस छिड़ जाती है। कोई 101 फीट का रावण बनाता है,तो कोई 151 फीट का। मानो रावण का कद जितना ऊँचा होगा,बुराई पर विजय उतनी ही शानदार होगी।

समझ में नहीं आता कि रावण को हराने की होड़ लगी है या उसे ऊँचा उठाने की। हर साल पुतले का कद बढ़ता है, आतिशबाजी का खर्च बढ़ता है, भीड़ बढ़ती है,जय श्रीराम के जयकारे गुँजते

हैं और अंत में रावण धू-धू करके जल उठता है। लोग तालियाँ बजाते हैं, मोबाइल से वीडियो बनाते हैं और घर लौटकर चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या रावण सचमुच जल गया? अगर रावण केवल दस सिरों वाला एक पुतला होता, तो मामला बहुत आसान था। एक माफिस की तीली लाई और बुराई का अंत! मगर आज के रावण के दस सिर नहीं, दसियों चेहरे हैं। कहीं वह भ्रष्टाचार बनकर बैठ है,कहीं रिश्त का मेज पर मुस्करा रहा है,कहीं गरीब का हक मार रहा है,तो कहीं अपने पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर रहा है। उसके चेहरे पर अच्छाई का मुवौटा है और जेब में स्वार्थ का हिसाब-किताब।

सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आधुनिक रावण को किसी सोने की लंका की जरूरत नहीं। उसे सरकारी दफ्तर की एक कुर्सी,किसी संस्था का



ऊँचा पद,सत्ता का संरक्षण या कानून की कमजोर पकड़ भी काफी है। वह दूसरों को नैतिकता का पाठ पढ़ता है

और खुद नियमों को अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लेता है। पकड़ा जाए तो जांच का इंतजार, आरोप लगे तो साजिश का शोर और सवाल पूछे जाएँ तो चुप्पी की दीवार! अब प्रश्न उठता है कि ऐसे रावणों का इलाज क्या है? क्या इनके लिए भी 151 फीट का पुतला बनाया जाए? क्या इनके नाम की आतिशबाजी हो? या फिर इनके पुतलों पर भी बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा जाए- 'बुराई पर अच्छाई की विजय' ! सच तो यह है कि इन रावणों के लिए पुतले जलाने से ज्यादा जरूरी है न्याय का दीप जलाना। कानून ऐसा हो जो गरीब और ताकतवर में अंतर न करे। जांच ऐसी हो जो रसूख के आगे न झुके और सजा ऐसी हो जो अपराधी को उसके अपराध के अनुसार मिले। केवल आरोप लगाना अपराध सिद्ध होना नहीं है, लेकिन प्रमाणित अपराधों पर कार्रवाई न होना न्याय व्यवस्था के

प्रति लोगों का विश्वास जरूर कमजोर करता है। विडंबना देखिए,हम हर साल रावण को जलाने का उत्सव मनाते हैं,लेकिन अपने भीतर बैठे अहंकार,लालच,छल और अन्याय को बचाकर रखते हैं। दूसरों के रावण का दहन हमें अच्छा लगता है, अपने भीतर के रावण से सामना करना नहीं। इसलिए इस दशहरे पर रावण की ऊँचाई नहीं,अपने चरित्र की गहराई नापिए। पुतले की राख से ज्यादा जरूरी है अन्याय की जड़ों को जलाना। क्योंकि असली विजय उस दिन होगी, जब 151 फीट का रावण जलाने के लिए मैदान में भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और समाज में बैठे रावण कानून से बचने के बजाय कानून का सम्मान करने लगेंगे। तब शायद दशहरा बलि एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि पूरे साल दिखाई देने वाली अच्छाई की पहचान बनेगा।

नवरात्रि विशेष : देवी का नवम स्वरूप सिद्धिदात्री

राजीव नंदन मिश्र, भोजपुर,बिहार
शारदीय नवरात्रि का आज नवम दिवस है। यह दिवस देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है। आज श्रद्धालु देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप का पूजन व आराधना करेंगे। नव दिनों तक उपवास रखकर विधि-विधान से देवी का पूजन कर श्रद्धालु अभीष्ट कामनाओं की पूर्ति हेतु माँ से प्रार्थना करेंगे। प्रथम दिवस को लिये गए संकल्प के बाद व्रत-पूजन का आज अंतिम दिवस है। सकल वातावरण वैदिक मंत्रोच्चारण से गुँज रहा एवं शुद्ध हो रहा हैं। आज ही समस्त देवी मन्दिरों व पंडालों में हवनारी भी किया जायेगा। भक्तजन देवी से अपने अपराधों के लिए भक्ता मांगकर मनवाछित वरदान भी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही श्रद्धालु सम्पत्तर व्यतीत होने के पश्चात अगले वर्ष पुनः देवी के आने का निवेदन भी करेंगे। हलांकि पंडालों से मूर्ति विसर्जन अगले दिन किया जायेगा। वहीं कई स्थानों पर दशहरा के दिन मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाता। नवरात्रि में नव दिनों तक भक्तों को उपवास रखकर जो आनन्द आता है वो आनन्द उपवास समाप्ति पर अनाज खाने के बाद नहीं मिल पाता। इन नव दिनों माँ के साक्षात सान्निध्य में रहने के बाद विसर्जन होने से भक्तों के आँखों में अश्रु आना स्वाभाविक है। परंतु माँ की कृपा अपने पुत्रों पर ह्दशरा बनी रहती है। आज इस वर्ष के शारदिय नवरात्रि के अंतिम दिवस पडिये देवी सिद्धिदात्री के स्वरूपादि के बारे में।



ध्यान मन्त्र -
सिद्धगन्धर्वशक्षाद्यैरसुरैरमरेण ।
सेव्यमाना सदा भूयत सिद्धिदा सिद्धिदायिनी ।।
 अर्थ-जो देवी सिद्धा,गंधर्वा,यक्षों,असुरों और देवताओं द्वारा भी सदा पूजित और सेवित हैं,जो समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली है,वो जगतजननी माँ सिद्धिदात्री सदैव हमारा कल्याण करें और हमें सिद्धि प्रदान करें।
मन्त्र - !! देवी सिद्धिदात्यै नमः !!
देवी सिद्धिदात्री की कथा -
 पुराणों के अनुसार भगवान शिवजी ने देवी मैया की घोर तपस्या की। भगवान शिवजी की तपस्या की देवी प्रसन्न हुई। शिवजी ने उनसे अष्ट सिद्धि प्रदान करने की प्रार्थना की। देवी ने शिवजी के इच्छनुसार उन्हें अष्ट सिद्धियाँ प्रदान की। जो अष्ट सिद्धियाँ भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री से प्राप्त की थी वो हैं-अणिमा,महिमा,गहिमा,लघिमा,प्राप्ति,प्राकाम्य,ईशित्व और वशित्व। ब्रह्मवेतंत्रपुराण के श्रीकृष्ण जन्म खंड में इन सिद्धियों की संख्या अठारह बताई गई है। समस्त सिद्धियों की देवी होने के कारण ही देवी का नाम सिद्धिदात्री है। धर्मग्रंथों के अनुसार यह भी प्राप्त होता हैं कि देवी आदिशक्ति ही माँ सिद्धिदात्री के रूप में भगवान शिव जी के बायें भाग में प्रकट हुई। अर्थात अर्द्ध भाग में स्वयं भगवान शिव एवं अर्द्ध भाग में स्वयं देवी। और तभी से भगवान शिवजी को अर्धनारीश्रव कहा जाता है।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटीक खबरें प्रकाशित करना है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अखिलभारत न्यायतंत्र के अधीन होगा।

सम्पादक

लेख एवं विचार अभिव्यक्ति

अम्बिकापुर सोमवार 19 अक्टूबर 2026

2

सत्ता परिवर्तन का रास्ता भीड़तंत्र नहीं,जनमत -लोकतंत्र से



सौरभ वाघण्य

परिवर्तन को लेकर बांग्लादेश जैसे घटनाक्रम का उदाहरण दिया जाता है या रिजोम्य चेंज अर्थात शासन व्यवस्था को बदलने की बात कही जाती है, तो इस विषय पर गंभीरता से विचार करना आवश्यक हो जाता है। भारत जैसे विशाल और परिपक्व लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का रास्ता संवैधानिक व्यवस्था, जनमत और शांतिपूर्ण आंदोलनों से होकर गुजरना चाहिए,न कि भीड़ के दबाव अथवा अराजकता से।

हाल के दिनों में विपक्ष पर भारत में भी बांग्लादेश की तर्ज पर सत्ता परिवर्तन की कोशिश करने के आरोप लगाए गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण के संदर्भ में भी रिजोम्य चेंज की बहस सामने आई है। ऐसे बयानों और आरोपों के मूल्यांकन राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप से ऊपर उठकर किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति के बयान का वास्तविक अर्थ उसके पूरे संदर्भ में समझना जरूरी है। केवल किसी शब्द के आधार पर किसी व्यक्ति या पूरे विपक्ष की मंशा पर अंतिम निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा। फिर भी, यदि सत्ता परिवर्तन का आशय संवैधानिक प्रक्रिया से बाहर जाकर सरकार को हटाने या व्यवस्था को अस्थिर करने से है,तो ऐसी सोच स्वस्थ

लोकतंत्र के लिए निश्चित रूप से चिंताजनक है।

भारत और बांग्लादेश की राजनीतिक, सामाजिक तथा संवैधानिक परिस्थितियों में अंतर है। भारत में नियमित चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका,निर्वाचन आयोग, संसद,राज्य विधान सभाएं और संवैधानिक संस्थाएं सत्ता परिवर्तन के स्थापित माध्यम हैं। इन संस्थाओं की मजबूती ही लोकतंत्र की स्थिरता सुनिश्चित करती है। किसी दूसरे देश में हुए राजनीतिक घटनाक्रम को भारत में दोहराने की कल्पना करना न तो आवश्यक है और न ही भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप।भारत की पहचान शांति,सहिष्णुता और संवाद की परंपरा से रही है। यहां सत्ता किसी व्यक्ति, दल या संगठन की स्थायी संपत्ति नहीं है। सरकारें आती-जाती हैं,लेकिन देश और उसकी संवैधानिक व्यवस्था सर्वोपरि रहती है। इसलिए किसी भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करना,जिनसे सामाजिक तनाव, हिंसा या संस्थागत अस्थिरता बढ़े, देशहित में नहीं हो सकता। लोकतंत्र और भीड़तंत्र के बीच स्पष्ट अंतर है। लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनी जाती है, असहमति का सम्मान होता है और निर्णय कानून तथा संवैधानिक प्रक्रियाओं के अनुसार लिए जाते हैं। इसके विपरीत, भीड़तंत्र में संख्या और दबाव के बल पर निर्णय थोपने की प्रवृत्ति पैदा हो सकती है। यदि किसी सरकार को हटाने के लिए सड़कों पर भीड़ जुटाकर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने या कानून-नियमों का आकलन नारों,शोराल मीडिया अभियानों या भीड़ के आकार से नहीं,बल्कि व्यापक जनमत और चुनावी प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। यदि किसी सरकार की नीतियां जनविरोधी हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती या शासन में गंभीर कमियां दिखाई देती हैं,तो विपक्ष का दायित्व है कि वह इन मुद्दों को जनता के सामने रखे। उसे वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करनी चाहिए,



का विरोध करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण विरोध,धरना, प्रदर्शन, जनसभाएं और जनजागरण लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। जब जनता किसी नीति,निर्णय या शासन के तरीके से असंतुष्ट होती है,तो उसे अपनी आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। आवश्यक यह है कि आंदोलन शांतिपूर्ण,लोकतांत्रिक और संवैधानिक दायरे में रहे।

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। यदि जनता किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है,तो उसके पास चुनाव में अपना मत देकर सरकार बदलने का अधिकार है। यही लोक तांत्रिक व्यवस्था का सबसे प्रभावी और वैध माध्यम है। किसी सरकार की लोकप्रियता का आकलन नारों,शोराल मीडिया अभियानों या भीड़ के आकार से नहीं,बल्कि व्यापक जनमत और चुनावी प्रक्रिया से किया जाना चाहिए। यदि किसी सरकार की नीतियां जनविरोधी हैं, जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरती या शासन में गंभीर कमियां दिखाई देती हैं,तो विपक्ष का दायित्व है कि वह इन मुद्दों को जनता के सामने रखे। उसे वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करनी चाहिए,

रहकर किया जाए।

विपक्ष का काम केवल सत्ता का विरोध करना नहीं,बल्कि एक जिम्मेदार विकल्प प्रस्तुत करना भी है। इसी तरह, सत्तापक्ष को भी आलोचना से घबराने के बजाय जनता की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। लोकतंत्र में असहमति को देशविरोधी मानना गलत है, लेकिन असहमति के नाम पर हिंसा या संवैधानिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का समर्थन भी नहीं किया जा सकता।

भारत की लोकतांत्रिक शक्ति उसकी जनता, संविधान और संस्थाओं में निहित है। यहां सत्ता परिवर्तन का अधिकार जनता को है और उस अधिकार की रक्षा करना प्रत्येक राजनीतिक दल का कर्तव्य है। रिजोम्य चेंज' जैसी बहसों में शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण उनका आशय और अपनाया जाने वाला रास्ता है। यदि उद्देश्य जनहित में शासन सुधारना और चुनाव के माध्यम से सरकार बदलना है, तो वह लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन यदि उद्देश्य भीड़ के दबाव से संवैधानिक व्यवस्था को अस्थिर करना है, तो उसका विरोध होना चाहिए।

भारत अराजकता का नहीं,बल्कि शांति,सहिष्णुता और लोकतांत्रिक संवाद का देश है। यहां सरकारों का भविष्य जनता वय करे,न कि हिंसक भीड़ या असंवैधानिक दबाव। सरकार जनता की इच्छा के विरुद्ध चलती है तो जनता उसे बदल सकती है,लेकिन यह परिवर्तन संविधान और कानून के रास्ते से होना चाहिए। लोकतंत्र की असली जीत किसी सरकार की हार में नहीं, बल्कि जनता की इच्छा,संविधान की सर्वोच्चता और देश की एकता की रक्षा में है। यही भारत की लोकतांत्रिक परंपरा है और यही देश को सही दिशा में आगे ले जाने का मार्ग भी।

खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा तक

— डॉ. प्रियंका सौरभ,हिसार,हरियाणा—

खाद्यान्न की उपलब्धता के साथ संगुलित आहार,टिकाऊ कृषि और प्रभावी वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करना समय की मांग खाद्य सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि,सामाजिक न्याय और मानवीय विकास का आधार है। जिस देश के नागरिकों को पर्याप्त,सुरक्षित और पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं होता,वहाँ विकास के बड़े-बड़े दावे भी अधूरे रह जाते हैं। भारत ने स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति की है। हरित क्रांति से लेकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के विस्तार तक, देश ने खाद्य संकट से उबरकर खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की दिशा में लंबी यात्रा तय की है। आज भारत दुनिया के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल है। इसके बावजूद कुपोषण,एनीमिया,खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें,जलवायु परिवर्तन और खाद्यान्न वितरण में असमानता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। इसलिए अब आवश्यकता केवल अनाज के भंडार भरने की नहीं,बल्कि प्रत्येक नागरिक तक संतुलित,पौष्टिक और सुरक्षित भोजन पहुँचाने की है। विश्व खाद्य दिवस 2026 की प्रस्तावित थीम'इनोवेट टुडे,नॉरिश टुमॉरो'अर्थात आज नवाचार करें,कल पोषण सुनिश्चित करें'खाद्य सुरक्षा के भविष्य में नवाचार की भूमिका को रेखांकित करती है। बदलती जलवायु,बढ़ती आबादी और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के बीच खाद्य व्यवस्था को अधिक टिकाऊ,समावेशी और तकनीक आधारित बनाना आवश्यक है।

भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,2013 इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कानूनी आधार मिला। इस व्यवस्था ने गरीब और कमजोर परिवारों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने करोड़ों लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करार संकट के समय सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण प्रदर्शित किया। जनवरी 2024 से पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत पाँच वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था लागू की गई। इससे गरीब परिवारों पर खाद्य व्यय का बोझ कम करने में सहायता मिली। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई द्वारा खाद्यान्न की खरीद, भंडारण और वितरण तथा बफर स्टॉक का रखरखाव देश की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के महत्वपूर्ण आधार हैं। न्यूतम समर्थन मूल्य के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अनाज जुटाने का प्रयास किया जाता है। हालाँकि,इस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए खरीद प्रक्रिया में विविधता लाने की आवश्यकता है,ताकि गेहूँ और धान के साथ दलहन,तिलहन तथा मूले अनाजों को भी पर्याप्त प्रोत्साहन मिल सके।

खाद्य वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग भी उल्लेखनीय है। 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी सुविधा के अनुसार राशन प्राप्त करने की सुविधा मिली है। विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों के लिए यह पहल महत्वपूर्ण है। आधार आधारित प्रमाणिकरण,राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों और डिजिटल निगरानी ने वितरण प्रणाली में सुधार की संभावनाएँ बढ़ाई हैं। फिर भी तकनीकी गड़बड़ियों,नेटवर्क की समस्या और प्रमाणिकरण में विफलता के कारण किसी जरूरतमंद व्यक्ति को राशन से वंचित नहीं होना चाहिए। तकनीक का उद्देश्य सुविधा बढ़ाना होना चाहिए,न कि पात्र नागरिकों के लिए नई बाधाएँ खड़ी करना। खाद्य सुरक्षा का वास्तविक अर्थ केवल पेट भरना नहीं,बल्कि शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण उपलब्ध कराना भी है। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना यानी पीएम-पोषण के अंतर्गत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में बच्चों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों, किशोरियों,गर्भवती महिलाओं और स्तनापन कराने वाली माताओं के पोषण स्तर में सुधार पर ध्यान दिया जाता है। आंगनवाड़ी सेवाएँ,प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी इस दिशा में योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों के सुदृढीकरण यानी फोर्टिफिकेशन के माध्यम से आयरन, फोलिक एसिड और अन्य आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालाँकि,इन उपायों के साथ विविध आहार,स्वच्छ पेयजल,स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करनी होगी।

इन प्रयासों के बावजूद भारत में कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी गंभीर चिंता का विषय है। भोजन की पर्याप्त कैलोरी उपलब्ध होने के बावजूद यदि उसमें प्रोटीन, विटामिन,खनिज और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी है,तो व्यक्ति स्वस्थ जीवन नहीं जी सकता। महिलाओं और बच्चों में एनीमिया,बच्चों की वृद्धि में रुकावट और कम वजन जैसी समस्याएँ इस चुनौती को स्पष्ट करती हैं। गरीबी,खाद्य पदार्थों की कीमतें, जामरुकता की कमी और अस्तुलित खानपान इसके प्रमुख कारण हैं। इसलिए खाद्य सुरक्षा की नीतियों को पोषण सुरक्षा के व्यापक लक्ष्य से जोड़ना होगा। जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा के सामने एक और बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। अनियमित मानसून, सूखा, बाढ़, लू और बढ़ते तापमान का प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। गेहूँ जैसी फसलों पर अत्यधिक तापमान का प्रतिकूल असर पड़ सकता है,जबकि धान की खेती में अत्यधिक जल उपयोग भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ता है। यदि कृषि उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करके बढ़िया जाएगा,तो भविष्य में खाद्य सुरक्षा स्वयं संकट में पड़ सकती है। इसके अलावा,भंडारण की अपर्याप्त सुविधाओं,शीत शृंखला की कमी और परिवहन संबंधी समस्याओं के कारण फल,सब्जियाँ तथा अन्य शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थों की बर्बादी होती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे पहले कृषि उत्पादन को विविधतापूर्ण और टिकाऊ बनाना होगा। किसानों को दलहन, तिलहन, बाजरा, ज्वार और अन्य पौष्टिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मोटे अनाज कम पानी में उगाए जा सकते हैं और पोषण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। फसल विविधीकरण से किसानों की आय बढ़ने, मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने और जल संसाधनों पर दबाव कम करने में सहायता मिल सकती है। इसके साथ ही सूखा सहन करने वाली बीज किस्में,सूक्ष्म सिंचाई,मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और मौसम आधारित कृषि सलाह को बढ़ावा देना चाहिए।

824 संक्रमितों में 801 को इलाज,अब मां से बच्चे में संक्रमण रोकने पर जोर

एचआईवी नियंत्रण में सरगुजा को मिली 'सुरक्षित' श्रेणी,अब 'सुरक्षित प्लस' की तैयारी

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 18 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

एचआईवी संक्रमण की पहचान के बाद मरीजों को उपचार से जोड़ना और संक्रमण को आगे फैलने से रोकना सरगुजा स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिकता बन गया है। जिले में अब तक 824 एचआईवी संक्रमितों की पहचान की गई है, जिनमें से 801 का एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) के तहत उपचार शुरू किया जा चुका है। उपचारित मरीजों में 99 प्रतिशत से अधिक वायरल लोड सप्रेमन दर्ज होने के साथ जिले ने मिशन एड्स सुरक्षा अभियान में 'सुरक्षित' श्रेणी हासिल की है। अब स्वास्थ्य विभाग का जोर गर्भवती महिलाओं की जांच, संक्रमित माताओं का समय पर उपचार और नवजातों को संक्रमण से बचाने पर है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (नाको) के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय एड्स एवं यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सरगुजा ने यह उपलब्धि हासिल की है। कलेक्टर अजीत



बसंत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम से जुड़े अमले ने जांच, उपचार और मरीजों की नियमित निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया। इस उपलब्धि के साथ सरगुजा प्रदेश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है।
जांच से लेकर उपचार तक निगरानी : जिले में एचआईवी संक्रमितों

की पहचान के साथ उन्हें नियमित उपचार उपलब्ध कराने और वायरल लोड की निगरानी की जा रही है। दिशा टीम, एकीकृत परामर्श एवं जांच केंद्र, एआरटी केंद्र और प्रयोगशाला सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों की इसमें अहम भूमिका है। स्वास्थ्य विभाग का प्रयास है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति जांच और उपचार से वंचित न रहे।

संभाग स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता : कोटया और सरगुजा इलेवन ने दर्ज की जीत,बलसेड़ी ने शंकरगढ़ को हराया

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 18 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।
 गांधी स्टेडियम में आयोजित संभाग स्तरीय नॉकआउट कम लीग फुटबॉल प्रतियोगिता 2026 के सेकंड राउंड में रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। निर्धारित समय तक मुकाबला बराबरी पर रहने के बाद बलसेड़ी ने टाईब्रेकर में जीत दर्ज की। वहीं,कोटया और सरगुजा इलेवन ने भी अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले दौर की ओर कदम बढ़ाया।



पहला मुकाबला शंकरगढ़ और कपसरा के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने बेहतर तालमेल के साथ गोल करने के प्रयास किए,लेकिन निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी। इसके बाद टाईब्रेकर में बलसेड़ी की टीम ने 5-4 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया।

दूसरे मुकाबले में कोटया और धर्मयोगी की टीमों आमने-सामने रहीं। पहले हाफ में दोनों टीमों ने एक-एक गोल किया। दूसरे हाफ में कोटया ने अंतिम समय में

एक और गोल दागकर मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर लिया। तीसरे मैच में सरगुजा इलेवन ने अम्बिकापुर यूनाइटेड को 1-0 से हराया। पहले हाफ में सरगुजा इलेवन ने गोल कर बहुत बनाई। दूसरे हाफ में दोनों टीमों कोई गोल नहीं कर सकी और सरगुजा इलेवन ने जीत हासिल की।
आज खेले जाएंगे दो मुकाबले : प्रतियोगिता में 19 अक्टूबर को दो मैच खेले जाएंगे।

होटल में नाशता करने रुका चालक, पीछे लुढ़ककर 200 मीटर दूर भट्टे में घुसा तेल टैंकर

होटल में खड़ी बुलेट टैंकर के नीचे दबी...



—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 18 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

रायपुर से अम्बिकापुर की ओर जा रहा एक तेल टैंकर उदयपुर क्षेत्र के ग्राम खंडागांव में हादसे का शिकार हो गया। रविवार सुबह करीब 11.30 बजे चालक सड़क किनारे एक होटल में नाशता करने रुका था। इसी दौरान टैंकर अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगा और करीब 200 मीटर दूर स्थित दूसरे होटल में जा घुसा। हादसे में होटल में खड़ी एक बुलेट टैंकर के नीचे दब गई। प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार,पीछे की ओर लुढ़कता टैंकर दूसरे होटल के भट्टे में जा घुसा और वहां जल रहे

भट्टे तक पहुंच गया। गनीमत रही कि टैंकर में आग नहीं लगी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। एहतियात के तौर पर होटल के मिस्त्री ने दोनों भट्टों पर पानी डालकर आग बुझा दी।
पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुंची : घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी निरीक्षक शिशिरकांत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। संभावित खतरे को देखते हुए अदाणी कोल माइंस की फायर ब्रिगेड टीम को भी बुलाया गया। एहतियात के तौर पर टैंकर के आसपास लोगों की आवाजाही रोक दी गई,ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

सात साल में 11 हजार से अधिक कुत्तों का रेस्क्यू,अब घायल तीन घोड़ों को भी दिया सहारा

बेजुबान डॉग शेल्टर में 210 कुत्तों समेत अन्य पशुओं की देखभाल,जनसहयोग से चल रहा सेवा कार्य

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 18 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

घायल,बीमार और बेसहारा पशुओं को नया जीवन देने की कोशिश में जुटा बेजुबान डॉग शेल्टर पिछले सात वर्षों से सेवा कार्य कर रहा है। इस दौरान शेल्टर की टीम 11 हजार से अधिक कुत्तों का रेस्क्यू कर चुकी है। वर्तमान में यहां 210 कुत्तों के साथ बिल्लियों,घोड़ों और अन्य जरूरतमंद पशुओं की देखभाल की जा रही है। हाल ही में टीम ने जशपुर से आगे के क्षेत्र से घायल अवस्था में मिले तीन घोड़ों का रेस्क्यू कर उन्हें उपचार के लिए शेल्टर पहुंचाया। शेल्टर के सुधांशु शर्मा ने बताया कि टीम का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायल,गंभीर रूप से बीमार और परित्यक्त पशुओं को समय पर सहायता उपलब्ध कराना है। रेस्क्यू के बाद पशुओं के भोजन,दवाइयों, उपचार और सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था की



जाती है। कई पशुओं को चोट या बीमारी के कारण लंबे समय तक देखभाल की जरूरत होती है। हाल ही में रेस्क्यू किए गए तीनों

घोड़ों के पैरों में चोटें थीं। उन्हें सुरक्षित तरीके से शेल्टर लाया गया, जहां उनकी देखभाल और उपचार किया जा रहा है। यह पहल

बताती है कि शेल्टर की टीम कुत्तों के साथ अन्य जरूरतमंद पशुओं की मदद के लिए भी प्रयासरत है।

जनसहयोग से चल रहा सेवा कार्य

शेल्टर का संचालन मुख्य रूप से जनसहयोग और दान से होता है। यहां रह रहे पशुओं के लिए प्रतिदिन भोजन, दवाइयों और इलाज की व्यवस्था करना बड़ी जिम्मेदारी है। रेस्क्यू और परिवहन पर भी खर्च होता है। ऐसे में शेल्टर ने समाज के लोगों और पशु प्रेमियों से सहयोग की अपील की है। सुधांशु शर्मा के अनुसार,लोगों का छोटा-सा सहयोग भी किसी घायल पशु के इलाज,भूखे जानवर को भोजन और बेसहारा पशु को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने में मददगार हो सकता है। शेल्टर का उद्देश्य बेजुबानों को सुरक्षित जीवन और बेहतर देखभाल उपलब्ध कराना है।

31 नग लोहे का खंभा बरामद,आरोपी हिरासत में

वन विभाग की कार्रवाई,300 नग चोरी हुई है तबड़े का खंभा,कनों की सुरक्षा के लिए लोहे के खंभा गाड़कर फिर गए थे फेंकिंग



—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 18 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

मैनपाट के कमलेश्वरपुर वन परिक्षेत्र में जंगल की सुरक्षा के लिए की गई फेंकिंग के करीब 300 लोहे के खंभे चोरी होने का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने मुखबि की सूचना पर कमलेश्वरपुर निवासी अजीत गुप्ता के घर छापेमारी कर 31 खंभे बरामद किए हैं। मामले में अजीत को हिरासत में लिया गया है। वहीं,चोरी के बाकी खंभों और मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। मैनपाट रेंजर प्रशांत ओहदार ने बताया कि कमलेश्वरपुर वन परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट नंबर 2464, नागादांड में जंगल की सुरक्षा के लिए लोहे के खंभे गाड़कर फेंकिंग की गई थी। इसी क्षेत्र से अज्ञात लोगों ने करीब 300 खंभे चोरी कर लिए थे। वन विभाग की टीम चोरी गए खंभों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अजीत गुप्ता ने अपने घर में चोरी के खंभे रखे हैं। टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और 31 खंभे बरामद कर लिए। रेंजर के अनुसार,पूछताछ में अजीत ने किसी अन्य व्यक्ति से खंभे खरीदने की बात बताई है। उसकी निशानदेही पर मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। चोरी गए शेष खंभों को बरामदगी के प्रयास भी जारी हैं।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन

—संवाददाता—
 जशपुरनगर, 18 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।
 आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला जशपुर द्वारा मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना शिक्षण सत्र 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान निम्न आय वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के उच्च व्यावसायिक संस्थानों जैसे IIT, AIIMS, IIM, NLU, MBBS, NIT, IIIT में प्रवेश प्राप्त किया है, उन्हें इस योजना के तहत ताल्कालिक सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक या स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 30 अक्टूबर 2026 तक कार्यालयीन समय प्रातः 10 से शाम 5 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास जशपुर में जमा कर सकते हैं। आवेदन फार्म विभागीय पोर्टल <https://eklavya.cg.nic.in/> या कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं होगा। पात्रता - विद्यार्थी छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो, अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो, पालक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो। शासकीय सेवक के आश्रित पात्र नहीं होंगे, केवल चतुर्थी श्रेणी कर्मचारियों के बच्चे पात्र होंगे।

शक की आग में उजड़ गया घर: मोबाइल पर बात करने और बेटे को ले जाने की जिद पर पति ने डंडे से पीटकर की पत्नी की हत्या

—संवाददाता—
 राजपुर, 18 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोटागहना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चरित्र शंका के चलते एक पति ने अपनी ही पत्नी की लकड़ी के डंडे से निर्मम हत्या कर दी। राजपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

क्या है पूरा मामला : पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 16 अक्टूबर 2026 को ग्राम कोटागहना के उपसरपंच अनिल तिवारी (पिता नारद तिवारी, उम्र 53 वर्ष) ने राजपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गांव के ही रहने वाले रामवृक्ष कोरवा उर्फ पिंटू (पिता जगम कोरवा,उम्र 35 वर्ष) ने अपनी पत्नी चिंतामणि कोरवा की लकड़ी के डंडे से मारपीट कर हत्या कर दी है। प्रार्थी की लिखित रिपोर्ट पर थाना राजपुर में अपराध क्रमांक

256/2026, धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

क्यों हुई खौफनाक वारदात? पुलिस जांच और गवाहों के बयानों से खुलासा हुआ कि आरोपी रामवृक्ष अपनी पत्नी चिंतामणि के चरित्र पर शक करता था। घटना वाले दिन मृतिका मोबाइल फोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति से बात कर रही थी और साथ ही अपने दो वर्षीय बेटे रमेश कोरवा को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ी हुई थी। इसी बात से गुस्साए आरोपी ने घर में रखे लकड़ी के डंडे से अपनी पत्नी के सिर पर तांबड़ोटोड़ वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

त्वरित कार्रवाई और बरामदगी : मामले की गंभीरता को देखते हुए राजपुर पुलिस ने फौरन एक्शन लिया। विवेचना के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का डंडा और मृतिका के खून से सने कपड़े जब्त कर लिए हैं। पर्याप्त सबूत मिलने पर आरोपी रामवृक्ष कोरवा



को 17 अक्टूबर 2026 की शाम 19:10 बजे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। मामले में आगे की विवेचना जारी है।

धान छोड़ रागी उगाई,अब 10 हजार रुपये के प्रोत्साहन का इंतजार

कृषक उन्नति योजना से फसल विविधीकरण को बढ़ावा,लेकिन किसान की असली कमाई का हिसाब कटाई के बाद ही सामने आएगा...

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 18 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

धान की खेती के लिए पहचाने जाने वाले छत्तीसगढ़ में अब किसानों को दूसरी फसलों की ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड के परसा गांव के किसान दिनेश कुमार यादव ने इसी पहल के तहत एक एकड़ में धान की जगह रागी (मड़िया) की खेती की है। कृषि विभाग ने उन्हें बीज उपलब्ध कराया और तकनीकी मार्गदर्शन भी दिया।



फसल की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। अब कृषक उन्नति योजना के तहत प्रति एकड़ 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की उम्मीद है। हालांकि, रागी की फसल लहलहाने और प्रोत्साहन राशि मिलने की उम्मीद के बीच एक सवाल भी अहम है—क्या वैकल्पिक फसल अपनाने से किसान की आमदनी वास्तव में बढ़ेगी? इसका जवाब फिलहाल फसल की कटाई, वास्तविक उत्पादन, बाजार में मिलने वाले दाम और खेती की कुल लागत का हिसाब सामने आने के बाद ही मिलेगा।
बीज मिला, तकनीकी सलाह मिली, अब उत्पादन पर नजर : किसान

दिनेश कुमार यादव के मुताबिक,कृषि विभाग ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उन्हें रागी का बीज उपलब्ध कराया था। विभागीय अधिकारियों के मार्गदर्शन में उन्होंने एक एकड़ में इसकी खेती की। उनके अनुसार, नियमित सलाह और देखरेख से फसल की बढ़ावर अच्छी हुई है। अधिकांश फसल तैयार हो चुकी है, जबकि शेष फसल भी अच्छी स्थिति में है। फिलहाल फसल की स्थिति को सफलता

का संकेत माना जा रहा है,लेकिन किसान को इससे कितना आर्थिक लाभ होगा,यह अभी तय नहीं है। वास्तविक उत्पादन, कटाई के बाद मिलने वाले दाने,बिक्री की व्यवस्था और बाजार भाव का आकलन होने पर ही रागी की खेती की आर्थिक तस्वीर स्पष्ट होगी।

किसान को उम्मीद, अब नतीजों की बारी

दिनेश यादव ने रागी की फसल की अच्छी स्थिति पर संतोष जताते हुए प्रधानमंत्री,मुख्यमंत्री और कृषि विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया है। अब कटाई के बाद उत्पादन और आमदनी का वास्तविक आकलन होगा। उनकी पसल दूसरे किसानों को भी धान के अलावा अन्य फसलें अपनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। हालांकि, इस पहल की असली सफलता तभी मानी जाएगी,जब किसान को लागत निकालने के बाद उचित लाभ मिले और वैकल्पिक खेती के लिए आर्थिक रूप से टिकाऊ साबित हो।

—संवाददाता—
 अम्बिकापुर, 18 अक्टूबर 2026
 (घटती-घटना)।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतिम स्नातक, स्नातकोत्तर,डिप्लोमा एवं पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की दिसंबर-2026 सेमेस्टर परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) एवं सीबीसीएस प्रणाली के तहत आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी 25 अक्टूबर तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों को आवेदन पत्र की हार्डकॉपी और आवश्यक दस्तावेज

संबंधित महाविद्यालय में 26 अक्टूबर तक जमा करना अनिवार्य है। महाविद्यालयों को 27 अक्टूबर तक आवेदन पत्रों की जांच और ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। इसके बाद सत्यापित आवेदन पत्र एवं संबंधित दस्तावेज 28 से 30 अक्टूबर तक विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने होंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा आवेदन,हार्डकॉपी जमा करने और ऑनलाइन सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही पोर्टल पर सतत आंतरिक मूल्यांकन (सीआईए) एवं प्रायोगिक परीक्षा के अंकों की ऑनलाइन प्रविष्टि की जा सकेगी। ऐसे में महाविद्यालयों के प्राचार्यों और शिक्षकों को निर्धारित समय-सीमा में सभी प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।

10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि से कितनी बदलेगी तस्वीर?

दिनेश यादव ने बताया कि कृषि विभाग के अधिकारियों से उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत धान के स्थान पर निर्धारित वैकल्पिक फसलों की खेती करने पर प्रोत्साहन राशि मिलने की जानकारी मिली थी। इसके बाद उन्होंने रागी की खेती का निर्णय लिया और योजना के लिए पंजीयन भी कराया है। योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता पूरी होने पर उन्हें एक एकड़ के लिए 10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलने की उम्मीद है। यह राशि किसान के लिए खेती की लागत का बोझ कम करने में मददगार हो सकती है। लेकिन केवल प्रोत्साहन राशि के आधार पर किसी वैकल्पिक फसल को अधिक लाभकारी नहीं माना जा सकता। इसके लिए बीज, खाद,मजदूरी,कटाई,परिवहन और बिक्री पर होने वाले खर्च की तुलना धान की खेती से करना भी जरूरी है।

मिलेट को बढ़ावा देना आसान,बाजार तक पहुंच बनाना असली चुनौती

रागी जैसे मोटे अनाज पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और फसल विविधीकरण में इनकी भूमिका भी अहम है। इसके बावजूद किसानों के सामने उत्पादन के साथ उपज की बिक्री, उचित मूल्य और नियमित खरीदार उपलब्ध होने जैसी चुनौतियां रहती हैं। यदि किसान को बाजार में उचित दाम नहीं मिलता, तो अच्छी फसल के बावजूद अपेक्षित आर्थिक लाभ हासिल करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कृषि विभाग और शासन की जिम्मेदारी केवल बीज वितरण और तकनीकी मार्गदर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। किसानों को उपज की खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था भी मजबूत करनी होगी,ताकि वैकल्पिक फसलों की खेती महज प्रोत्साहन राशि तक सीमित न रह जाए।

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने किया 'हैलो जी हेल्थकेयर' का शुभारंभ, एक क्लिनिक पर मिलेंगी डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं...

ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श,वीडियो कंसल्टेशन,क्लिनिक अपॉइंटमेंट और डायग्नोस्टिक सेवाओं को एक मंच पर लाने की पहल

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को भी घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श लेने का मिलेगा अतिरिक्त विकल्प

-संवाददाता-

रायपुर/एमसीबी, 18 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक नई पहल करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अपने गृह ग्राम रतनपुर स्थित कार्यालय में डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म 'हैलो जी हेल्थकेयर' का शुभारंभ किया, मंत्री ने बटन दबाकर वेबसाइट www.Hellozy.in/Healthcare का उद्घाटन किया, इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से मरीजों और चिकित्सकों को डिजिटल रूप से जोड़ना तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को अधिक सुविधाजनक बनाना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान की भावना और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शुरू की गई इस पहल के माध्यम से मरीजों को ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श,वीडियो कंसल्टेशन,अस्पताल एवं क्लिनिक में अपॉइंटमेंट तथा डायग्नोस्टिक सेवाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है,प्लेटफॉर्म पर स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने और दवाइयों के ऑर्डर जैसी सुविधाओं को भी शामिल किए जाने की जानकारी दी गई है।

डिजिटल तकनीक से स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होगी आसान-शुभारंभ अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी



जायसवाल ने कहा कि आधुनिक तकनीक स्वास्थ्य सेवाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, डिजिटल माध्यमों के विस्तार से मरीजों को चिकित्सकों से परामर्श लेने,उपचार के लिए अपॉइंटमेंट प्राप्त करने और आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी हासिल करने में सहूलियत मिल सकती है, उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और सुविधाजनक बनाने के लिए तकनीक आधारित नवाचारों को प्रोत्साहित करना समय की आवश्यकता है,इस तरह के प्रयास मरीजों के

समय की बचत करने के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच बेहतर बनाने में सहायक हो सकते हैं।

एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी कई सुविधाएं- 'हैलो जी हेल्थकेयर' को एक इंटीग्रेटेड केयर नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया है,इसका उद्देश्य मरीजों और चिकित्सकों के बीच डिजिटल संपर्क स्थापित कर परामर्श और अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को सरल बनाना है।

प्लेटफॉर्म के माध्यम से मरीजों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराने की

जानकारी दी गई है:

- **ऑनलाइन डॉक्टर परामर्श :** डिजिटल माध्यम से चिकित्सकों से परामर्श लेने की सुविधा।
 - **वीडियो कंसल्टेशन :** वीडियो कॉल के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श बुक करने का विकल्प।
 - **क्लिनिक एवं अस्पताल अपॉइंटमेंट :** उपचार के लिए अग्रिम समय निर्धारित करने की सुविधा।
 - **डायग्नोस्टिक सेवाएं :** आवश्यक जांच संबंधी सेवाओं तक पहुंच का विकल्प।
 - **दवाइयों के ऑर्डर :** दवाइयों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर की व्यवस्था।
 - **डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड :** स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखने की सुविधा, इन सुविधाओं का उद्देश्य मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए एक ही डिजिटल मंच उपलब्ध कराना है।
- मरीजों और चिकित्सकों के लिए अलग-अलग पोर्टल-प्लेटफॉर्म पर मरीजों के लिए अलग लॉगिन और चिकित्सकों के लिए स्वतंत्र पोर्टल की व्यवस्था की गई है, इससे मरीजों को परामर्श एवं अपॉइंटमेंट संबंधी प्रक्रिया पूरी करने और चिकित्सकों को डिजिटल माध्यम से मरीजों से जुड़ने में मदद मिल सकती है, वेबसाइट पर 24 घंटे हेल्पलाइन और त्वरित टेली-कंसल्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराने

की जानकारी भी दी गई है,इससे मरीजों को जरूरत के अनुसार संपर्क और परामर्श प्राप्त करने का अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है, हालांकि,इन सुविधाओं की वास्तविक उपलब्धता,संबंधित चिकित्सकों की उपलब्धता और सेवाओं की पहुंच का आकलन इनके संचालन तथा उपयोगकर्ताओं के अनुभव के आधार पर किया जा सकेगा।

ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के मरीजों को मिल सकता है लाभ-छत्तीसगढ़ के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए चिकित्सकीय परामर्श तक समय पर पहुंच एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, ऐसे क्षेत्रों में किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए मरीजों को कई बार दूसरे शहरों की यात्रा करनी पड़ सकती है,डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म इस स्थिति में एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकता है,ऑनलाइन परामर्श और वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मरीज सामान्य स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं,डिजिटल अपॉइंटमेंट से अस्पताल या क्लिनिक में निर्धारित समय पर पहुंचने की योजना बनाने में भी मदद मिल सकती है, हालांकि,डिजिटल परामर्श हर स्थिति में प्रत्यक्ष चिकित्सकीय जांच का विकल्प नहीं है। गंभीर लक्षणों, आपातकालीन परिस्थितियों और ऐसी बीमारियों में जिनमें शारीरिक परीक्षण या तत्काल उपचार की आवश्यकता हो,मरीजों को उपयुक्त स्वास्थ्य केंद्र में जाना जरूरी होगा,

डिजिटल सेवाओं का लाभ इंटरनेट कनेक्टिविटी और संबंधित सेवाओं की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा।

डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में पहल

'हैलो जी हेल्थकेयर' का शुभारंभ स्वास्थ्य सेवाओं में डिजिटल तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक पहल है, एक ही मंच पर चिकित्सकीय परामर्श,अपॉइंटमेंट और अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं को उपलब्ध कराने का उद्देश्य मरीजों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाना है,अब इस पहल की उपयोगिता इस बात से तय होगी कि प्लेटफॉर्म पर कितने चिकित्सक और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जुड़ते हैं,ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों तक इसकी पहुंच कितनी बनती है और मरीजों को सेवाएं कितनी सहजता से उपलब्ध हो पाती हैं, डिजिटल सुविधाओं का प्रभावी संचालन, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी की गोपनीयता और मरीजों को विश्वसनीय चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध कराना भी इसकी सफलता के महत्वपूर्ण पहलू होंगे,फिलहाल,स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल द्वारा 'हैलो जी हेल्थकेयर' का शुभारंभ प्रदेश में डिजिटल माध्यमों से स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

ट्रैक्टरों की बेलगाम दौड़ में उजड़ रहे परिवार,अखिर कब जागेगा प्रशासन ?

शुक्रवार को विश्रामपुर में 13 वर्षीय छात्रा की मौत,शनिवार को कुबेरपुर में महिला ने गंवाई जान...गिट्टी लदे ट्रैक्टरों के संचालन पर उठा सवाल



सूरजपुर पुलिस ने दशहरा पर्व के लिए जारी किया पार्किंग

मैप,शहर में पिकअप वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

सुगम यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित,अगसेन चौक से कार्यक्रम स्थल की ओर वाहनों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

-संवाददाता-

सूरजपुर, 18 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

दशहरा पर्व के दौरान शहर में सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूरजपुर पुलिस ने पार्किंग स्थल एवं वाहनों के आवागमन का मैप जारी किया है। दिनांक 20 अक्टूबर 2026 को दशहरा पर्व के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सूरजपुर श्री योगेश कुमार पटेल (भापुसे) के निर्देश पर यातायात पुलिस ने बेहतर यातायात प्रबंधन की तैयारी की है। पुलिस ने नागरिकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन खड़े करने तथा यातायात व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

दशहरा पर्व के दिन शहर में पिकअप वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं,कार्यक्रम स्थल की ओर वाहनों से आने वाले लोगों के लिए अग्रसेन चौक से आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। चारपहिया वाहन चालक बड़कापारा एवं मानपुर चौक मार्ग से होते हुए कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे तथा अपने वाहनों को हार्डस्कूल ग्राउंड में निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करेंगे।

प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी वाहनों के लिए निर्धारित मार्ग : यातायात प्रभारी बुजकिशोर



पाण्डेय ने बताया कि बुधवार,21 अक्टूबर 2026 को मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन के उपरांत सभी भारी वाहन बाईपास रिंग रोड,महगवाा होते हुए भैयाथान रोड की ओर जाएंगे। इस व्यवस्था का उद्देश्य शहर के भीतर यातायात का दबाव कम करना तथा आम नागरिकों के आवागमन को सुचारु बनाए रखना है।

यातायात नियमों का पालन करने की अपील : यातायात पुलिस ने नागरिकों से दशहरा पर्व के दौरान निर्धारित मार्गों एवं पार्किंग व्यवस्था का पालन करने की अपील की है। साथ ही शराब का सेवन कर वाहन नहीं चलाने, दोपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं बैठाने तथा यातायात नियमों का पालन करने की समझावश दी है।

-संवाददाता-
सूरजपुर, 18 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जिले में गिट्टी लदे ट्रैक्टरों से हो रहे हादसों ने सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुक्रवार को विश्रामपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर गिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से 13 वर्षीय छात्रा रिद्धिमा जैन की दर्दनाक मौत हो गई। वह अपने पिता के साथ स्कूल में आयोजित पैरेंट्स मीटिंग से घर लौट रही थी। इस घटना का दुख अभी कम भी नहीं हुआ था कि शनिवार को चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के कुबेरपुर में गिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से चंद्रावती जायसवाल की जान चली गई। दो दिनों में दो दर्दनाक हादसों ने एक बार फिर ट्रैक्टरों की आवाजाही, परिवहन नियमों के पालन और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, फिर गिट्टी परिवहन में नियमों का पालन कितना ? ट्रैक्टर मूल रूप से कृषि कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाला वाहन है, लेकिन आज कई क्षेत्रों में इनका उपयोग गिट्टी, रेत और अन्य निर्माण सामग्री के परिवहन में भी किया जा रहा है। सवाल यह है कि ऐसे व्यावसायिक परिवहन में क्या वाहन की अनुमति,पंजीयन,फिटनेस,चालक की पात्रता और अन्य लागू नियमों का पालन किया जा

रहा है? जहां बिना जरूरी अनुमति या नियमों के विपरीत परिवहन हो रहा है, वहां जिम्मेदारों पर कार्रवाई कौन करेगा? विशेषकर आबादी वाले क्षेत्रों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर गिट्टी लदे ट्रैक्टरों की आवाजाही के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। हालांकि,प्रत्येक ट्रैक्टर से होने वाले परिवहन को अवैध कहना उचित नहीं होगा,संबंधित वाहनों के दस्तावेजों और संचालन की जांच के बाद ही नियमों के उल्लंघन की स्थिति स्पष्ट होगी।

शुक्रवार को स्कूल से लौट रही छात्रा की मौत : 16 अक्टूबर को विश्रामपुर क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग-43 पर दर्दनाक हादसा हुआ। सूरजपुर नवापारा निवासी एलआईसी एजेंट पंकज कुमार जैन अपनी 13 वर्षीय पुत्री रिद्धिमा जैन के साथ कामेल कॉन्टेंट स्कूल में आयोजित पैरेंट्स मीटिंग से बाइक पर घर लौट रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे गिट्टी लदे ट्रैक्टर क्रमांक सीजी 15 सीक्यू 5992 को क्रॉस करते समय ट्रैक्टर चालक द्वारा अचानक वाहन मोड़ने से बाइक टकरा गई। पिता-पुत्री सड़क पर गिर पड़े और रिद्धिमा का सिर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई,जबकि पिता को हल्की चोटें आईं। ट्रैक्टर के बाद ट्रैक्टर सड़क किनारे स्थित एक मकान में जा घुसा। सूचना पर



विश्रामपुर थाना प्रभारी निरीक्षक विकास देशमुख पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रैन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर को बाहर निकलवाकर जब्त किया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मासूम की मौत से परिवार और स्कूल में शोक का माहौल है।

शनिवार को कुबेरपुर में महिला की मौत, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा : विश्रामपुर की घटना के अगले दिन शनिवार को चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के कुबेरपुर में एक और दर्दनाक हादसा सामने आया। जानकारी के अनुसार, संजय जायसवाल की पत्नी चंद्रावती जायसवाल बिहारपुर चौक से पूजा का सामान लेकर स्कूटी से घर लौट रही थीं। इसी दौरान गिट्टी लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद चालक के वाहन सहित मौके से फरार होने की जानकारी सामने आई। ग्रामीणों का कहना है कि बस्ती के बीच संचालित क्रेशर और वहां से गुजरने वाले गिट्टी लदे वाहनों को लेकर लंबे समय और शव रखकर मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान क्रेशर परिसर में आगजनी भी हुई। मौके पर पहुंचे एसडीओपी, थाना प्रभारी और तहसीलदार को भी आक्रोशित भीड़ ने घेर लिया। अधिकारियों को बंधक बनाए जाने

और उनके साथ कथित मारपीट की खबरें सामने आईं। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही।

लदखों के बाद कार्रवाई नहीं, पहले से निगरानी जरूरी

लगातार सामने आ रही दुर्घटनाएं यह सवाल उठाती हैं कि क्या संबंधित विभाग वाहनों की नियमित जांच और सड़क सुरक्षा के प्रति पर्याप्त सतर्क हैं? गिट्टी लदे ट्रैक्टरों की गति,चालक की लापरवाही,वाहन के दस्तावेज,परिवहन की वैधता और आबादी वाले क्षेत्रों में आवाजाही जैसे पहलुओं की जांच जरूरी है। यदि कहीं नियमों का उल्लंघन हो रहा है,तो समय रहते कार्रवाई होनी चाहिए,ताकि किसी और परिवार को ऐसा दुःख न झेलना पड़े। दो दिनों में दो परिवारों की खुशियां उजड़ गईं। शुक्रवार को एक मासूम छात्रा की जिंदगी खत्म हुई,तो शनिवार को एक महिला की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया। अब जरूरत केवल हादसों के बाद कार्रवाई करने की नहीं, बल्कि ऐसे इंतजाम करने की है,जिनसे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कृषि कार्य के लिए बने ट्रैक्टरों का अन्य परिवहन कार्यों में इस्तेमाल नियमों के अनुरूप हो और सड़क पर आम लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता न हो।

नव संकल्प शिक्षण संस्थान में नए बैच के लिए प्रवेश परीक्षा एक नवंबर को

सीजीपीएससी,सीजी एसएसबी और एसएससी जीडी की नि:शुल्क प्रतियोगी परीक्षा तैयारी का मिलेगा अवसर

-संवाददाता-
जशपुरनगर, 18 अक्टूबर 2026
(घटती-घटना)।

जिला प्रशासन जशपुर द्वारा संचालित नव संकल्प शिक्षण संस्थान में नए बैच में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर से शुरू होगी। जिले के युवाओं को विभिन्न राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क तैयारी कराने के उद्देश्य से संस्थान द्वारा प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 26 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। नवसंकल्प शिक्षण संस्थान में नए सत्र के तहत छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) राज्य सेवा

प्रारंभिक परीक्षा, छत्तीसगढ़ व्यापम, एसएसबी से संबंधित पटवारी, अमीन एवं छात्रावास अधीक्षक जैसी भर्ती परीक्षाओं तथा कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) जीडी परीक्षा की तैयारी के लिए बैच संचालित किए जाएंगे।

इसके माध्यम से युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन एवं अध्ययन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। नए बैच में प्रवेश के लिए परीक्षा एक नवंबर को ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसके लिए जिले के चार परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं,जिनमें जशपुर, कुनकुरी,पथलगांव और बगीचा शामिल हैं।



सरगुजा में महिला एवं बाल विकास विभाग की संविदा भर्ती पर विवाद

अनुभव प्रमाण-पत्रों, पात्रता और चयन समिति की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल



सरगुजा में संविदा भर्ती पर सवालों का घेरा, अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच की मांग... फर्जी अनुभव का आरोप, पात्रता पर विवाद... महिला बाल विकास विभाग की भर्ती सवालों में...

पहले अपात्र, फिर पात्रता पर सवाल!

सरगुजा की संविदा भर्ती में कथित दोहरी मापदंड

गंभीर सर्जरी सरकारी अस्पताल में संभव तो प्रसूता को स्थानीय स्तर पर ऑपरेशन की सुविधा कितनी सुलभ? स्वास्थ्य सेवाओं के दावों के बीच मातृ स्वास्थ्य व्यवस्था की समीक्षा जरूरी

संविदा भर्ती में किस पर मेहरबानी? अनुभव प्रमाण-पत्रों को लेकर कलेक्टर से शिकायत

अनुभव प्रमाण-पत्रों पर विवाद, चयन समिति की भूमिका पर उठे सवाल

सरगुजा में भर्ती प्रक्रिया पर सवाल, अंतिम सूची से पहले जांच की मांग

किसी का अनुभव खारिज, किसी को पात्रता का लाभ? भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थी की आपत्ति

महिला बाल विकास विभाग की भर्ती में पारदर्शिता पर सवाल, कलेक्टर तक पहुंचा मामला

पीएमएमवीवाई ऑपरेटर पद के अभ्यर्थी ने कलेक्टर को सौंपी दावा-आपत्ति, अनुभव प्रमाण-पत्रों और चयन प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच की मांग

सरगुजा में संविदा भर्ती पर सवालों का घेरा, अनुभव प्रमाण-पत्रों से लेकर चयन समिति की भूमिका तक उठे गंभीर प्रश्न

महिला एवं बाल विकास विभाग की भर्ती प्रक्रिया पर विवाद, अनुभव की अवधि, शैक्षणिक योग्यता, वेतन भुगतान के प्रमाण और चयन समिति के निर्णयों की निष्पक्ष जांच की मांग

-न्यूज डेस्क-

अंबिकापुर, 18 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

सरकारी नौकरी पाने की उम्मीद लेकर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रिया केवल परीक्षा या मेरिट सूची तक सीमित नहीं होती, उनकी पात्रता का निर्धारण निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रमाण-पत्रों और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर किया जाता है, ऐसे में यदि किसी भर्ती प्रक्रिया में पात्रता निर्धारण को लेकर ही सवाल खड़े होने लगे, तो चयन समिति की कार्यप्रणाली और विभागीय पारदर्शिता की जांच की मांग उठना स्वाभाविक है, सरगुजा जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग में संविदा पदों पर भर्ती को लेकर सामने आई शिकायत ने इसी तरह के सवाल खड़े किए हैं। पीएमएमवीवाई यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर पद से

संबंधित पात्रता और अनुभव प्रमाण-पत्रों को लेकर अभ्यर्थी आशुतोष कश्यप ने 21 सितंबर 2026 को कलेक्टर, सरगुजा के समक्ष लिखित दावा-आपत्ति प्रस्तुत की है, शिकायत में मोहम्मद शहनवाज के अनुभव प्रमाण-पत्रों, शैक्षणिक योग्यता तथा पात्रता निर्धारण की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अंतिम सूची तैयार करने से पहले मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है, शिकायतकर्ता का आरोप है कि अनुभव के मूल्यांकन और पात्रता निर्धारण में सभी अभ्यर्थियों के लिए समान मानदंड अपनाए जाने चाहिए, लेकिन चयन प्रक्रिया में कथित विस्मंगति सामने आई है, आवेदन में पुराने चयन निर्णयों, अनुभव की अवधि और प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की मांग की गई है, हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए विभागीय अभिलेखों, चयन समिति के निर्णय और संबंधित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का परीक्षण जरूरी है, इसके बावजूद शिकायत ने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और पात्रता निर्धारण के आधार को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न अवश्य खड़े कर दिए हैं।

विज्ञापन से चयन सूची तक, कहां और कैसे तय हुई पात्रता?

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज विज्ञापन क्रमांक 937/स्था./मबावि./2023-24 है, जिसका उल्लेख शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में किया है, शिकायत में इस विज्ञापन की तारीख 6 अक्टूबर 2023 बताई गई है, आवेदक ने इसी भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्रों और पात्रता निर्धारण पर आपत्ति जताई है, आवेदन के अनुसार, मोहम्मद शहनवाज के संबंध में पूर्व चयन प्रक्रिया के दौरान अनुभव को लेकर आपत्ति की गई थी और उन्हें अपात्र किए जाने का उल्लेख है, शिकायतकर्ता ने सवाल उठाया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को अनुभव की कमी या दस्तावेजों के आधार पर अपात्र माना गया था, तो बाद में उनकी पात्रता स्वीकार किए जाने के पीछे क्या आधार रहा, यहां मूल प्रश्न किसी अभ्यर्थी के पक्ष या विपक्ष में निर्णय लेने का नहीं, बल्कि यह जानने का है कि चयन समिति ने नियमों की व्याख्या किस तरह की, क्या पहले और बाद के निर्णयों में कोई नया दस्तावेज प्रस्तुत किया गया था? क्या अनुभव प्रमाण-पत्रों का पुनः सत्यापन हुआ था? क्या चयन समिति ने अपने निर्णय में बदलाव के कारणों को लिखित रूप से दर्ज किया था? यदि किसी अभ्यर्थी ने दावा-आपत्ति के दौरान अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत किए और उन दस्तावेजों के आधार पर उसकी पात्रता स्वीकार की गई, तो यह नियमों के अनुरूप हो सकता है, लेकिन यदि समान परिस्थितियों में अलग-अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग मापदंड अपनाए गए हों,

इस मामले में प्रशासन निम्नलिखित बिंदुओं पर स्थिति स्पष्ट कर सकता है...

1. संबंधित पद के लिए जारी विज्ञापन की मूल शर्तें क्या थीं?
2. मोहम्मद शहनवाज के अनुभव प्रमाण-पत्रों का सत्यापन किस स्तर पर हुआ?
3. पूर्व में अपात्रता का निर्णय हुआ था तो उसके कारण क्या थे?
4. बाद की प्रक्रिया में पात्रता स्वीकार की गई हो तो उसके पीछे कौन-से नए दस्तावेज या नियमगत आधार थे?
5. अन्य अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच भी समान प्रक्रिया से हुई या नहीं?
6. आशुतोष कश्यप की 21 सितंबर 2026 की दावा-आपत्ति पर क्या निर्णय लिया गया?
7. अंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है या प्रक्रिया अभी लंबित है?

इन प्रश्नों का जवाब मिलने से भर्ती प्रक्रिया के बारे में तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सकती है, साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी अभ्यर्थी के अधिकारों का हनन न हो और सरकारी भर्ती में पारदर्शिता बनी रहे।

तो उस अंतर का स्पष्ट और दस्तावेजी आधार होना चाहिए, यही वह बिंदु है जिस पर जिला प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, चयन समिति के कार्यवृत्त, पात्र-अपात्र सूची, दावा-आपत्तियों के निराकरण और अंतिम निर्णयों का परीक्षण किए बिना विवाद का वास्तविक स्वरूप सामने नहीं आ सकता।

अनुभव प्रमाण-पत्र की वास्तविकता की जांच कैसे हुई?

शिकायत में अनुभव प्रमाण-पत्रों के आधार पर पात्रता स्वीकार किए जाने पर आपत्ति उठाई गई है, आवेदक ने अनुभव की अवधि और कार्य की प्रकृति की जांच की आवश्यकता बताई है, ऐसे मामलों में यह देखना महत्वपूर्ण होता है कि संबंधित अभ्यर्थी ने किस संस्थान में कार्य किया, उसका पदनाम क्या था, कार्य की वास्तविक प्रकृति क्या थी और अनुभव की अवधि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप थी या नहीं, केवल प्रमाण-पत्र पर अंकित तारीखों को देखकर अनुभव की वैधता का अंतिम निर्णय नहीं किया जा सकता, जरूरत पड़ने पर प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान से जानकारी मांगी जा सकती है, संस्थान के नियुक्ति आदेश, उपस्थिति रिकॉर्ड, कार्यमुक्ति प्रमाण-पत्र, भुगतान संबंधी अभिलेख और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का मिलान किया जा सकता है, इस मामले में भी सवाल यही है कि क्या संबंधित अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संस्थान से उसकी पुष्टि कराई गई थी? यदि कराई गई थी तो सत्यापन रिपोर्ट में क्या दर्ज है? और यदि कोई आपत्ति पहले सामने आई थी तो उसका निराकरण किस आधार पर किया गया? इन प्रश्नों का जवाब विभागीय रिकॉर्ड से मिलना चाहिए, किसी शिकायत या संदेह के आधार पर प्रमाण-पत्र को फर्जी घोषित करना उचित नहीं होगा, लेकिन प्रमाण-पत्र की वैधता पर विशिष्ट आपत्ति होने पर उसका सत्यापन करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है।

वेतन पर्वी और बैंक स्टेटमेंट का मुद्दा भी महत्वपूर्ण

अनुभव की पुष्टि के संबंध में वेतन भुगतान के दस्तावेज भी चर्चा में हैं, शिकायतकर्ता ने वेतन पर्वी और बैंक स्टेटमेंट जैसे प्रमाणों के आधार पर अनुभव की जांच की आवश्यकता जताई है, ऐसे दस्तावेज यह स्पष्ट करने में मदद कर सकते हैं कि संबंधित अवधि में अभ्यर्थी को वेतन भुगतान हुआ था या नहीं, हालांकि, वेतन पर्वी या बैंक स्टेटमेंट का अभाव अपने आप में यह साबित नहीं करता कि किसी व्यक्ति ने कार्य ही नहीं किया, यह भी देखा होगा कि संबंधित विज्ञापन और लागू भर्ती नियमों में कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य किए गए थे, यदि नियमों में वेतन भुगतान के प्रमाण की स्पष्ट मांग थी, तो सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की उसी कसौटी पर जांच की जानी चाहिए, यदि किसी विशेष परिस्थिति में वैकल्पिक प्रमाण स्वीकार किए गए, तो उसके पीछे नियमसम्मत आधार होना चाहिए, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि दस्तावेजों की कमी के कारण किसी अभ्यर्थी को अपात्र किया गया था तो क्या उसे नियमानुसार दावा-आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर मिला, इसी तरह, किसी दूसरे अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर उसके मामले में क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इस पूरे विवाद का समाधान आरोप-प्रत्यारोप से नहीं, बल्कि समान नियम, समान अवसर और निष्पक्ष दस्तावेजों जांच से ही संभव हो सकता है।

मिशन शक्ति की भर्ती और विभागीय विज्ञापन में क्या दर्ज है?

महिला एवं बाल विकास विभाग, सरगुजा के उपलब्ध दस्तावेजों में मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत महिला सशक्तीकरण केंद्र के संचालन के लिए संविदा पदों पर भर्ती का भी उल्लेख है, विभागीय प्रेस विज्ञापन के अनुसार, वर्ष 2026 में तीन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, इनमें जेंडर विशेषज्ञ, आर्टी ऑपरेटर और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक-एक पद शामिल था,

विज्ञापन में आवेदन की अंतिम तिथि 20 जुलाई 2026 निर्धारित होने की जानकारी दी गई थी, दस्तावेजों के साथ अनुभव संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करने तथा निर्धारित शर्तों के अनुसार उनकी जांच किए जाने का उल्लेख भी भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां एक आवश्यक तथ्य स्पष्ट करना होगा, शिकायतकर्ता के आवेदन में वर्ष 2023 के विज्ञापन का उल्लेख है, जबकि उपलब्ध प्रेस विज्ञापन वर्ष 2026 की भर्ती से संबंधित है, इसलिए दोनों प्रक्रियाओं को एक ही भर्ती मान लेना उचित नहीं होगा, यह पता लगाना जरूरी है कि शिकायत किस चयन सूची और किस पद के अंतिम निर्णय से संबंधित है तथा वर्ष 2026 के दस्तावेज उस शिकायत से सीधे जुड़े हैं या केवल विभाग की अलग भर्ती प्रक्रिया का संदर्भ देते हैं, यदि दोनों प्रक्रियाओं के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध है, तो विभाग को उसका दस्तावेजी स्पष्टीकरण देना चाहिए, यदि दोनों अलग-अलग भर्तियां हैं, तो उनके नियमों, विज्ञापनों और चयन सूचियों का अलग-अलग परीक्षण किया जाना चाहिए।

क्या चयन समिति के निर्णयों का रिकॉर्ड सार्वजनिक होगा?

भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, समिति का दायित्व केवल दस्तावेज जमा करना और सूची तैयार करना नहीं, बल्कि विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप पात्रता का निर्धारण करना भी है, जब किसी अभ्यर्थी की ओर से लिखित दावा-आपत्ति दी जाती है, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर विचार कर निर्णय लेना आवश्यक होता है, यदि आपत्ति स्वीकार की जाती है, तो उसके कारण दर्ज होने चाहिए, यदि आपत्ति खारिज की जाती है, तो उसका आधार भी स्पष्ट होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की मां-अंतिम सूची से पहले हो निष्पक्ष जांच

आशुतोष कश्यप ने अपने आवेदन में कलेक्टर से अनुरोध किया है कि उनकी दावा-आपत्ति पर विचार करते हुए अंतिम सूची तैयार करने से पहले निर्णय लिया जाए, आवेदन में अनुभव प्रमाण-पत्रों और पात्रता निर्धारण को लेकर उठाए गए सवालों की जांच करने की मांग की गई है, शिकायतकर्ता का पक्ष है कि यदि चयन प्रक्रिया में अलग-अलग अभ्यर्थियों के लिए अलग मापदंड अपनाए गए हैं, तो इससे पात्रता निर्धारण की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, उनका अग्रह है कि सभी संबंधित दस्तावेजों की जांच कर स्पष्ट निर्णय लिया जाए, इस मामले में प्रशासन के सामने जिम्मेदारी है कि शिकायत में उठाए गए सवालों का निष्पक्ष परीक्षण करना, जांच में यदि कोई अनियमितता सामने आती है तो लागू नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, वहीं, यदि आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो संबंधित अभ्यर्थी की पात्रता पर लगाए जा रहे संदेह का भी समाधान होना चाहिए।

महिला एवं बाल विकास विभाग की जवाबदेही भी जरूरी

महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं और बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निभाता है, ऐसे विभाग में संविदा नियुक्तियों की प्रक्रिया का निष्पक्ष और पारदर्शी होना विशेष महत्व रखता है, नियुक्तियों में अनिश्चितता या पात्रता को लेकर विवाद न केवल अभ्यर्थियों को प्रभावित करता है, बल्कि विभागीय प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े करता है, इसलिए शिकायत को केवल दो अभ्यर्थियों के बीच का विवाद मानकर नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, यदि पात्रता निर्धारण को लेकर वास्तविक विस्मंगति है, तो उनका समाधान प्रशासनिक स्तर पर होना चाहिए, वहीं, यदि निर्णय नियमों के अनुरूप लिए गए हैं, तो विभाग को दस्तावेजी आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, यह भी जरूरी है कि शिकायतकर्ता को उसकी आपत्ति पर लिए गए निर्णयों की जानकारी मिले और संबंधित अभ्यर्थियों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाए, इससे जांच की निष्पक्षता बनी रहेगी और भर्ती प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक विवाद की गुंजाइश कम होगी।

अब कलेक्टर के निर्णय पर टिकी निगाहें...

21 सितंबर 2026 को प्रस्तुत दावा-आपत्ति के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जिला प्रशासन ने इस पर क्या कार्रवाई की, क्या संबंधित विभाग से रिपोर्ट मांगी गई? क्या अनुभव प्रमाण-पत्रों की जांच के निर्देश दिए गए? क्या चयन समिति के निर्णयों की समीक्षा की गई? और क्या अंतिम सूची तैयार करने से पहले शिकायत के सभी बिंदुओं का निराकरण किया गया? उपलब्ध शिकायत-पत्र अपने आप में अनियमितता साबित नहीं करता, लेकिन पात्रता निर्धारण पर उठाए गए सवालों की जांच की मांग जरूर करता है, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता का अर्थ केवल सूची प्रकाशित कर देना नहीं, बल्कि उस सूची के पीछे अपनाई गई प्रक्रिया को भी नियमसम्मत और जवाबदेह बनाना है, यदि सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेज एक ही कसौटी पर परखे गए हैं, तो विभाग को इसे रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट करना चाहिए और यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों की अनदेखी सामने आती है, तो उसके लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, अब देखा होगा कि सरगुजा जिला प्रशासन इस दावा-आपत्ति पर क्या रुख अपनाता है और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब दस्तावेजों के आधार पर सामने आता है या नहीं।

मोरन नदी पुल का मंत्री रामविचार नेताम ने किया भूमिपूजन

महाअष्टमी पर चलगली क्षेत्र को 5.91 करोड़ के पुल की सौगात, जिला मुख्यालय की दूरी 15 किमी होगी कम

-संवाददाता-

बलरामपुर, 18 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण, जैव प्रौद्योगिकी, मछलीपालन तथा पशुधन विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने आज नवरात्रि की महाअष्टमी पर ग्राम कपिलदेवपुर में मोरन नदी पर बनने वाले उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग का विधिवत भूमिपूजन किया। लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, अम्बिकापुर यह पुल कपिलदेवपुर-



बसेरा मार्ग पर बनाएगा। इसके लिए 5.91.04 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति मिली है। पुल बनने से चलगली क्षेत्र के 12 से 15 गांवों के 15 से 20 हजार ग्रामीणों को जिला मुख्यालय बलरामपुर पहुंचने के लिए लगभग 15 किलोमीटर कम दूरी तय करनी होगी। 144 मीटर लंबे और 8.40 मीटर चौड़े इस पुल में 24-24 मीटर के 6 स्पैन होंगे। संरचना को मजबूत बनाने के लिए पाइल फंडेशन तकनीक अपनाई जाएगी। पुल के दोनों छोरों पर कुल 271

मीटर पहुंच मार्ग भी बनेगा। समारोह में उपस्थितजनों को संबोधित करते हुए मंत्री श्री नेताम ने कहा कि महाअष्टमी के शुभ अवसर पर क्षेत्रवासियों को यह सौगात मिली है। पुल न होने से ग्रामीणों को लंबे समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। व पुल बनने के बाद आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और रोजगार ग्रामीणों की सहज पहुंच में होंगे। उन्होंने बताया कि चलगली से रामानुजगंज सड़क को स्वीकृति मिल चुकी है और निविदा प्रक्रिया पूरी होते ही इसका निर्माण शुरू होगा।

-संवाददाता-

बलरामपुर, 18 अक्टूबर 2026 (घटती-घटना)।

कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन और जिला आबकारी अधिकारी श्री शशांक शर्मा के मार्गदर्शन में जिले में अन्य प्रांत की मिलावटी मदिरा के विरुद्ध अभियान जारी है। इसी क्रम में जिला स्तरीय आबकारी उड़नदस्ते ने चांदो थाना क्षेत्र के ग्राम खजुरियाडीह में कार्रवाई की। टीम ने 29 वर्षीय आरोपी अरविन्द कुमार, पिता रामचंद्र प्रसाद, के कब्जे से झारखंड राज्य में विक्रय हेतु निर्मित 11.6 बल्क लीटर



देशी मदिरा मसाला जब्त किया।

मौके से मिलावट के लिए धोकर रखी गईं 51 खाली शीशियां और शीशियों को सील पैक करने के लिए 560 ढक्कन भी बरामद

किए गए। इससे स्पष्ट है कि आरोपी दूसरे राज्य की मदिरा में मिलावट कर उसे दोबारा पैक करने की छतरी में था। आरोपी के विरुद्ध तैयारी में था। आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1)(क), 34(2), 36 एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की विवेचना परिवीक्षाधीन आबकारी उपनिरीक्षक मनीष कुमार चंदा कर रहे हैं। कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक चन्द्रदीप भगत और अभिषेक राजवाड़े, मुख्य आरक्षक श्री धर्मजीत राम शर्मा, आरक्षक श्री शामिल रहे।

ग्लैमर से परे,अपनी शर्तों पर किया काम,हिंदी सिनेमा की मर्दानी रानी मुखर्जी के सफर पर एक नजर

रानी मुखर्जी ने हिंदी सिनेमा में तीन दशक पूरे किए हैं,जहां उन्होंने अपनी शर्तों पर लोक से हटकर कई दमदार भूमिकाएं निभाईं।हिंदी सिनेमा में अपनी शर्तों पर तीन दशक बिताना कोई छोटी बात नहीं है,लेकिन रानी मुखर्जी ने इसे कर दिखाया है। आज दुनिया उन्हें मर्दानी सीरीज की जांबाज पुलिस अफसर शिवानी शिवाजी राय जैसी जबरदस्त भूमिकाओं से पहचानती है।

साल 1996 में किया था डेब्यू



मगर इस सफलता के पीछे एक ऐसी साहसी अभिनेत्री छिपी है,जिसने अधिकतर लोक से हटकर चौकाने वाले रोल चुने। आज से 30 साल पहले 18 अक्टूबर 1996 को प्रदर्शित अपनी पहली ही फिल्म राजा की आयेगी बारात में उन्होंने एक ऐसी लड़की का दर्द जिया,जिसे अपने बलाकारी से शादी करनी पड़ती है। वहीं अइया में वह एक ऐसी प्रेम दीवानी बनीं,जो सिर्फ खुशबू के अहसास पर अपना दिल हार बैठती

है। इसके बाद हिचकी में टारेट सिंड्रोम से जुझती टीचर बनकर उन्होंने दिखाया कि कमजोरियों को ताकत कैसे बनाया जाता है। नो वन किल्ड जेसिका से तलाश तक ऐसे किरदारों की सूची बहुत लंबी है, मगर निर्देशक से लेकर दर्शक तक भरोसा एक कि रानी है तो मुमकिन है!

नामचीन परिवार से है रानी का नाता

फिल्मी परिवार की विरासत रानी के खून में सिनेमा दौड़ता है। वह झांसी के नामचीन मजिस्ट्रेट रवींद्र मोहन मुखर्जी के पोते और निर्देशक राम मुखर्जी की बेटी हैं। उनके बड़े पापा शशधर मुखर्जी ने बाबू टाकीज और फिल्मिस्तान जैसे ऐतिहासिक स्टूडियोज की नींव रखी थी, जिन्होंने भारतीय सिनेमा का सुनहरा दौर गाया। उनके पिता ने दिलीप कुमार को लेकर सुपरहिट फिल्म लौडर बनाई थी।सुपरस्टार काजोल उनकी चचेरी बहन हैं। इतनी बड़ी फिल्मी विरासत होने के बाद भी रानी इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहती थीं। वह अक्सर कहती थीं, घर में पहले से ही इतनी अभिनेत्रियां हैं, मुझे कुछ अलग करना है। लेकिन मां कृष्णा मुखर्जी की मनुहार के आगे उन्हें झुकना पड़ा और उन्होंने अभिनय को महज एक प्रयोग की तरह शुरू किया।

चॉकलेटी हीरोइन से आगे

शुरुआती सफर आसान नहीं था। उनकी पहली फिल्म बाक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। पहचान मिली विक्रम भट्ट की गुलाम से,जिसमें आती क्या खंडाला गाने ने उन्हें रातों-रात हर दिल अजीज बना दिया, हालांकि वह पूरी तरह आर्मिगर खान की फिल्म थी। इसके बाद करण जौहर की ब्लाकबस्टर फिल्मों कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम ने उन्हें सफलता का स्वाद चखाया।फिर तो चलते चलते, हम तुम और वीर-जारा जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा की रोमांटिक क्वीन बना दिया। मगर रानी सिर्फ पेड़ों के इर्द-गिर्द नाचने वाली पारंपरिक हीरोइन बनकर खुश नहीं रहने वाली थीं। उनके भीतर का कलाकार कुछ और ही तलाश रहा था।

हर रोल में दिखाया दम

साल 2000 में आई बादल,बिच्छ और कमल हासन की हे राम जैसी फिल्मों से रानी ने साफ कर दिया कि वह पुरुषों के वर्चस्व वाली एक्शन फिल्मों में भी धाक जमा सकती हैं। इसके बाद मणिरत्नम की राजनीतिक थ्रिलर युवा में एक प्रताड़ित पत्नी का किरदार हो या संजय लीला भंसाली की ब्लैक में हेलेन केलर से प्रेरित एक मूक-बधिर लड़की का जीवंत अभिनय,रानी ने हर रोल में दर्शकों को झकझोरा। उन्होंने बहुत ही संजीदगी से व्यावसायिक सिनेमा के रत्नमर और समानांतर सिनेमा की गहराई के बीच संतुलन बनाया। दिल बोले हड़पिया में क्रिकेट खेलने की खालिर लड़के का भेष बदलना हो,या तलाश में एक ऐसी मां का दर्द जीना हो जो अपने मासूम बच्चे की मौत के सदमे से उबर नहीं पाती-रानी ने हर रूप में खुद को ढाला। हालांकि इनमें से कई फिल्में टिकट खिड़की पर नाकाम रहीं,लेकिन रानी के किरदारों की धार कभी कम नहीं हुई।

परदे पर दमदार वापसी

उनके इस सिनेमाई सफर का सबसे चमकीला पड़ाव था साल 2014 में आई मर्दानी। इसमें उन्होंने मुंबई पुलिस की सीनियर इंस्पेक्टर शिवानी शिवाजी राय बनकर अपराधियों के छ्के छुड़ा दिए। इस ऐतिहासिक कामयाबी के बाद,रानी ने मातुत्व और परिवार को वक्त देने के लिए सिनेमा से दूरी बना ली। यह उनके पति और फिल्म निर्माता आदित्य चोपड़ा थे, जिन्होंने रानी के भीतर की अभिनेत्री को फिर से जगाया।चार साल बाद उन्होंने हिचकी से ऐसी धमाकेदार वापसी की कि दुनिया देखती रह गई। मर्दानी की दमदार सीरीज तो थी ही, मिसेज चटर्जी वर्सेज नावें में अपने बच्चों के लिए दूसरे देश की सरकार से लड़ जाने वाली मां के किरदार में उन्होंने शानदार अभिनय का नया अध्याय लिख दिया।

मिल चुके हैं 8 फिल्मफेयर

उनके नाम आज आठ फिल्मफेयर पुरस्कार हैं। वह हिंदी सिनेमा इतिहास की इकलौती ऐसी अभिनेत्री हैं, जिन्होंने एक ही साल (2004) में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री (युवा के लिए) दोनों का फिल्मफेयर पुरस्कार अपने नाम किया। मिसेज चटर्जी वर्सेज नावें के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला तो वहीं इसी साल उन्हें महाराष्ट्र सरकार के प्रतिष्ठित राज कपूर सम्मान से भी नवाजा गया है।



नानी की फिल्म द पैराडाइज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म से राघव जुयाल ने तेलुगु सिनेमा में कदम रखा है। श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित यह फिल्म आप अब ऑनलाइन देख सकते हैं। नानी ने द पैराडाइज के साथ बड़े पद पर वापसी की,जो 2026 की मोस्ट अवेटेड तेलुगु फिल्मों में से एक है। श्रीकांत ओडेला द्वारा निर्देशित इस एक्शन ड्रामा फिल्म से राघव जुयाल ने भी तेलुगु सिनेमा में कदम रखा है। यह फिल्म 24 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी,जिसे दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। हालांकि,उसी समय रिलीज हुई कई अन्य फिल्मों की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा,जिन लोगों ने इसे सिनेमाघरों में नहीं देखा है। उनके लिए अब यह फिल्म डिजिटल स्ट्रीमिंग पर आ रही है।

द पैराडाइज ओटीटी रिलीज

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने घोषणा की है कि द पैराडाइज 22 अक्टूबर 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। नानी और राघव जुयाल अभिनीत इस फिल्म को ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आठ भाषाओं - तेलुगु, हिंदी,तमिल,अंग्रेजी,स्पेनिश,बंगाली, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज करने का प्लान बनाया गया है।



रश्मिका मंदाना ने रणबीर की जगह अल्लू अर्जुन को चुना

सलमान खान द्वारा लोकप्रिय चैट शो,कॉफी विद करण के अंतिम सीजन के लिए टोन सेट करने के बाद,प्रिय जोड़ी विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना को दूसरे एपिसोड के लिए एक साथ सोफे पर देखा गया। यह शो में रश्मिका की शुरुआत का प्रतीक है,जबकि वीडी पहले ही अपनी लाइगर सह-कलाकार अनन्या पांडे के साथ कॉफी विद करण में दिखाई दे चुके हैं। यह एपिसोड युगल द्वारा किए गए स्पष्ट खुलासों से भरा था। शो के रैपिड फायर सेक्शन के दौरान,मेजबान और फिल्म निर्माता करण जौहर ने रश्मिका से उनके एनिमल के सह-कलाकार रणबीर कपूर और पुष्पा के सह-कलाकार अल्लू अर्जुन के बीच चयन करने के लिए कहा। द गलॉफ़्रेड अभिनेता ने बाद वाले को चुना। बाद में, जब करण ने विजय से पूछा कि उन्हें लगता है कि वह रश्मिका के अलावा किसके साथ सबसे अच्छी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री साझा करते हैं, तो उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए कहा, कोई नहीं। इस पर विजय ने खुलासा किया कि खुशहाल शादी के लिए उनका मंत्र सरल है,हमेशा अपनी पत्नी से सहमत रहें। अपने निजी

जीवन के बारे में कुछ और रोमांचक खुलासे करते हुए,विजय और रश्मिका ने साझा किया कि कैसे इस साल की शुरुआत में शादी के बंधन में बंधने से पहले उन्हें उनसे 100 बार पछुता पड़ा था। हाल ही में जारी प्रोमो में केजेओ ने रश्मिका और वीडी से पूछा, क्या कोई प्रस्ताव था? जैसे ही रश्मिका ने अपना सिर हिलाया, विजय ने खुलासा किया,उसने कहा,चलो शादी कर लें। मैंने कहा,ठीक है,आपने मुझसे 100 बार पूछा है। जैसा कि करण ने रश्मिका से पुष्टि की कि क्या उसने वास्तव में अर्जुन रेड्डी अभिनेता से शादी के लिए 100 बार पूछा था, उसने साझा किया,मैंने उससे पूरे एक साल का समय मांगा।विजय ने तब स्पष्ट किया,मैं कोई मूर्ख नहीं हूं, जैसे ही वे एपिसोड के गेमिंग सेगमेंट के पास पहुंचे,विजय ने अल्लू अर्जुन को फोन किया और उनसे अब-प्रतिष्ठित लाइन, करण, इसमें मौ देने के लिए कहा। लंबे समय तक अपने प्रशंसकों को उनके रिश्ते की स्थिति के बारे में अनुमान लगाने के बाद, विजय और रश्मिका ने आखिरकार 26 फरवरी को उदयपुर के आईटीसी मेमेंटोस में एक पारंपरिक समारोह में शादी कर ली।

खेल-समाचार

22 अक्टूबर को न्यूजीलैंड टीम से इंडिया का मुकाबला

क्राइस्टचर्च,18 अक्टूबर 2026।

वेस्टइंडीज सीरीज के बाद भारतीय टीम 22 अक्टूबर से न्यूजीलैंड दौरे का आगाज करेगी,जहां 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। टी20 सीरीज का पहला मैच 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में होगा जिसकी कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। वनडे सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होगी।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज 2-2 की बराबरी पर खत्म होने के बाद अब फैस की नजरें भारतीय टीम के आगले असाइमेंट पर टिक गई हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ अंतिम मैच के महज 4 दिन बाद भारतीय टीम को न्यूजीलैंड दौरे का आगाज करना है। भारत के इस न्यूजीलैंड दौरे की शुरुआत 22 अक्टूबर से 5 मैचों की टी20 सीरीज के साथ होगी। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में



भारतीय टीम के पास न्यूजीलैंड पहुंचने, वहां के ठंडे मौसम व रिंग्स कडीशंस में ढलने और प्रैक्टिस करने के लिए केवल 4 दिनों का कम समय होगा, जो खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है।

क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा पहला टी 20 आई दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा मैच

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। इसके दो दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को दूसरा टी20 भी इसी मैदान पर होगा, जिससे भारतीय खिलाड़ियों को शुरुआती दो मैचों के बीच ट्रेवल नहीं

करना पड़ेगा। तीसरा टी20 27 अक्टूबर को वेलिंगटन,चौथा 30 अक्टूबर को ऑकलैंड और पांचवां मुकाबला 1 नवंबर को हैमिल्टन में खेला जाएगा। सभी टी20 मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होंगे, जबकि टॉस दोपहर 12: 00 बजे होगा। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टी20 टीम में भुवी, मयंक यादव, तिलक वर्मा और

वैभव सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं।

टी 20 के बाद वनडे सीरीज में लौटेंगे रोहित-विराट

1 नवंबर को टी20 सीरीज खत्म होने के बाद 4 नवंबर से 5 मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत होगी। वनडे फॉर्मेट में फैस को अगर फिर रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गजों का एक्शन देखने को मिलेगा। पहले तीन वनडे मैचों में शुभमन गिल टीम इंडिया की कप्तान संभालेंगे। इसके बाद गिल और कुछ अन्य सीनियर खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए ब्रेक लेते, जिसके चलते आखिरी दो वनडे मुकाबलों में श्रेयस अय्यर कप्तानी करेंगे। वनडे मैचों के बाद 19 नवंबर से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें शुभमन गिल की कप्तानी में केएल राहुल, जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत मैदान में उतरेंगे।

ईशान किशन ने 3 चौके लगाकर तोड़ा रिजवान-सूर्या का रिकॉर्ड

बेंगलुरु,18 अक्टूबर 2026। ईशान किशन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को पीछे छोड़ते हुए यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। बारिश की वजह से ये मुकाबला रह हो गया, लेकिन इस मैच में ईशान किशन ने अपनी 30 रनों की पारी के दौरान नया इतिहास रच दिया। उन्होंने ये 30 रन 10 रेंदों में बनाए और एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। किशन ने अपनी इस पारी के दौरान 2 छक्के और 3 चौके भी लगाए। इस तीन चौके और दो छक्कों के साथ ही उन्होंने

मोहम्मद रिजवान और सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ आखिरी टी20 मैच में ईशान किशन ने 3 शानदार चौके लगाए और इसके साथ ही वह टी 20 इंटरनेशनल क्रिकेट में फुल-मैंबर टीमां के बीच एक साल में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने साल 2021 में कुल 119 चौके लगाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। किशन ने साल 2026 में अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 122 चौके लगाकर मोहम्मद रिजवान को 5 साल पुराना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस मामले में किष्वाब्बे के ब्रायन बनेट साल 2025 में 109 चौकों के

साथ तीसरे नंबर पर हैं। वहीं चौथे नंबर पर भारत के सूर्यकुमार यादव हैं, उन्होंने साल 2022 में 106 चौके लगाए थे। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम साल 2021 में 99 चौके लगाकर पांचवें स्थान पर हैं। टी20 आई में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा चौके लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज (फुल मेंबर टीम) इस पारी के दौरान ईशान किशन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा बाउंड्री (चौके-छक्के) लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने साल 2022 में 174 बाउंड्री लगाई थीं। ईशान साल 2026 में अब तक 34 मैचों में 177 बाउंड्री (122 चौके और 55 छक्के) लगाकर इस सूची में पहले नंबर पर पहुंच गए हैं।

एकता बिश्नोई ने जीते 3 गोल्ड



नई दिल्ली,18 अक्टूबर 2026। भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी एकता बिश्नोई ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ल्ड मास्टर्स क्लासिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में तीन स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज

16 दिसंबर को गोवा में होगी आईपीएल 2027 की मिनी नीलामी



नई दिल्ली,18 अक्टूबर 2026। सूत्रों ने बताया कि इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 2027 सीज़न के लिए मिनी नीलामी 16 दिसंबर को गोवा में होने की संभावना है। हालांकि टीम मालिकों और सीईओ को ईमेल के माध्यम से औपचारिक संचार अभी तक नहीं भेजा गया है, कई टीमों के सूत्रों और प्रसारण पक्ष ने पुष्टि की है कि नीलामी 16 दिसंबर को होने की संभावना है। यह भी समझा जाता है कि 14 दिसंबर को होने वाली नीलामी के लिए शुरुआती सुगबुगाहट थी। हॉ.बीसीसीआई ने 16 दिसंबर को होने वाली नीलामी के लिए सभी दस टीमों के प्रतिनिधियों को व्हाट्सएप के माध्यम से एक टेक्स्ट संदेश भेजा था, जिसमें नीलामी ब्रीफिंग एक दिन पहले 15 दिसंबर को की जानी थी। सूत्रों ने आगे कहा,वे सिर्फ यह जानना चाहते थे कि नीलामी के लिए आने वाली सभी दस टीमों के लोगों की संख्या कितनी होगी ताकि आईटीसी ग्रांड होटल में उनके लिए बुकिंग जल्द से जल्द शुरू की जा सके। संभावित आईपीएल 2027 मिनी नीलामी की तारीख का मतलब यह भी होगा कि 16 दिसंबर को बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दूसरे वनडे में भारत का श्रीलंका से मुकाबला होने की संभावना है।

प्रियदर्शन की 99 वीं फिल्म में बाघ शिकारी बनेंगे अक्षय कुमार



बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार 1970 के दशक की एक कॉमेडी फिल्म के लिए प्रियदर्शन के साथ फिर से काम करने जा रहे हैं।कॉमेडी टाईमिंग में अभिनेता अक्षय कुमार का एक अलग ही मुकाम है। वहीं अगर उनकी फिल्म प्रियदर्शन के साथ हो तो बात ही अलग है। निर्देशक-एक्टर की इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा को कई बेहतरीन फिल्में दी है। उनकी पिछली रिलीज भूत बंगला और हैवान थी। अब उन्होंने एक और कॉमेडी फिल्म के लिए हाथ मिलाया है।

प्रियदर्शन की 99वीं फिल्म में काम करेंगे अक्षय

अक्षय कुमार एक नए कॉमेडी प्रोजेक्ट के लिए अनुभवी फिल्म निर्माता प्रियदर्शन के साथ काम करने जा रहे हैं। यह निर्देशक की 99वीं फीचर फिल्म होगी। रमेश तौरानी द्वारा निर्मित इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं हुआ है। इस प्रोजेक्ट के साथ,अभिनेता और निर्देशक की यह सफल जोड़ी एक बार फिर साथ आ रही है।

फिल्म में अक्षय बनेंगे टाइगर हंटर

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म में वे 1970 के दशक की पृष्ठभूमि में एक अनोखे बाघ शिकारी का किरदार निभाएंगे।

